खबर पेज 6 पर

गंभीर समाचार

समय-समाज-संस्कृति

खबर पेज 8 पर

वर्ष -12 | अंक-29 | पाक्षिक समाचार पत्रिका | कोलकाता, शनिवार 16 - 31 मई 2026 | मूल्यः 5 रुपये | RNI No.WBHIN/2014/59321, ISSN No. 2456/3005 Kolkata | कुल पृष्ठ - 8

सुविचार

- जीवन में शांति चाहते हैं तो दुसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें। क्योंकि पुरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है।
- अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए..विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है!

शेरो-शायरी

- किसी ने फूल से पूछा की जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ "फूल ने जवाब दिया तोड़ने वाला इतना खुश था की मैं अपना दर्द भी भूल गया!
- तू किताब है जिसमें कहानियां बहुत है, मैं वो कागज़ हूं जो कोरा बहुत है, तू वो चाँद है जिसकी रोशनी बहुत है, और मैं वो रात हूं जिसमें अंधेरा बहुत है!
- मोहब्बत के अगर 100 हिस्से किये जाये तो 99 हिस्सों की हकदार हमारी माँ है।

सीएम शुभेंदु ने महिलाओं को दिया भरोसा

सरकारी अधिकारी घर-घर जाकर 'अन्नपूर्णा' के फॉर्म भरने में करेंगे मदद

निज संवाददाता : अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म को लेकर महिलाओं के एक समूह में भ्रम है। कई लोग इस बात को लेकर भ्रम में हैं कि 13 पेज का लंबा फॉर्म कैसे भरें। इसको लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सभी को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी घर-घर जाकर फॉर्म भरने में मदद करेंगे। शनिवार को उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम से कहा-बिल्कुल परेशान मत होइए। हमारे लोग घर-घर जाकर फॉर्म भरने में मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि सिर्फ असली हकदारों को ही मदद मिले। इससे पहले, महिला और बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल, मंत्री दिलीप घोष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा था कि फॉर्म को आसान बनाया जाएगा।

अन्नपूर्णा योजना के 13 पेज के फॉर्म को लेकर फैले भ्रम पर सीएम शुभेंदु ने महिलाओं को भरोसा देते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी घर-घर जाकर इस योजना का फॉर्म भरने में मदद करेंगे। उन्होंने महिलाओं से कहा-बिल्कुल परेशान मत होइए। हम चाहते हैं कि सिर्फ असली हकदारों को ही मदद मिले।

शनिवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी विधाननगर अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का उद्घाटन करने आए और महिलाओं को भरोसा दिलाया। यह कहते हुए कि असली हकदारों को ही पैसा मिलेगा, उन्होंने कहा-परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लोग घर जाकर मदद करेंगे। आपकी सरकार नियमों के मुताबिक सारा काम करेगी। यह सरकार प्रस्ताव के हर वाक्य और शब्द को पूरा करेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बुधवार को नवान्न से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म निकाला था।

इस दौरान मंत्री अग्निमित्रा पॉल, राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल और अन्य अधिकारी मौजूद थे। तब से कई लोगों को इस 13 पेज के फॉर्म से दिक्कतें आ रही हैं। उस दिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि फॉर्म भरने में सरकारी मदद दी जाएगी। शनिवार को उन्होंने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि वे चिंता न करें। वहीं, जो लोग फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं, 2 जून को कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्हें 3,000 रुपये की मदद मिलनी शुरू हो जाएगी।

महाराष्ट्र में जहरीली शराब से 15 की मौत

निज संवाददाता : महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ इलाकों में जहरीली शराब पीने से करीब 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। इस भयावह घटना के बाद राज्य और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले पर संज्ञान लेकर 8 संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर बताया है कि पूरे अवैध शराब के इकोसिस्टम का पता लग गया है, जिस पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह चौंकाने वाली घटना पुणे के काले पड़ल, हडपसर और पिंपरी-चिंचवाड़ के दापोडी, फुगेवाड़ी जैसे इलाकों से सामने आई है, जहां लोगों ने अवैध रूप से निर्मित जहरीली शराब का सेवन किया। जानकारी के अनुसार, जहरीली शराब का सेवन करने वाले लोगों की हालत अचानक बिगड़ी, उनके मुंह से झाग निकलने लगा और इलाज मिलने से पहले ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया।

भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है

सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी

निज संवाददाता : सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को फिर से कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाता है, तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अबकी सेना प्रमुख ने फिर से इस्लामाबाद को कड़ा संदेश दिया है।न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा-ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। हालांकि, उन्होंने मौजूदा हालात को शत्रुता की कुछ समय के लिए समाप्ति भी बताया। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा-इंडियन आर्मी और तीनों ब्रांच ऑपरेशन 2.0 की तैयारी कर रही हैं। फिलहाल, हम अपने आपसी तालमेल को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं। हम अगली लड़ाई के लिए खुद को 247 तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने यह भी कहा-युद्ध का मैदान इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि हर हरकत दूसरी तरफ को पता होती है। इसलिए, हमें बॉर्डर इलाकों में अपने सैनिकों को तैनात करने, उनका इस्तेमाल करने और आम लोगों की सुरक्षा करने में बहुत सावधान रहना होगा। मालूम हो कि 22 अप्रैल 2025 को लश्कर के शैडो ऑर्गनाइज़ेशन टीआरएफ के चार आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निहत्थे लोगों को मार डाला था। इस हमले के जवाब में भारत ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकवादी कैंप तबाह कर दिए गए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत की सीमा से लगे राज्यों में आबादी वाले इलाकों और आर्मी बेस पर हमला किया। भारत ने हमले का जवाब दिया और कम से कम 11 पाकिस्तानी एयर बेस तबाह कर दिए। भारतीय सेना के ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा आतंकवादी और 35-40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आखिर में, इस्लामाबाद के कहने पर नई दिल्ली सीज़फ़ायर के लिए मान गया। 88 घंटे के ऑपरेशन ने आतंकवाद के अड्डे को तबाह कर दिया था। अगर पाकिस्तान ने ऐसा हमला दोहराने की हिम्मत की, तो भारतीय सेना प्रमुख ने चेतावनी दी कि इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे।

टाटा ग्रुप को सिंगूर में वापस लाएंगे : शमिक भट्टाचार्य

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बड़ा प्रयास किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि टाटा समूह को सिंगूर या राज्य के किसी अन्य हिस्से में वापस लाने के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। उनका मानना है कि टाटा की वापसी बंगाल की औद्योगिक छवि को मजबूत करेगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगी। मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) द्वारा आयोजित 'रीइग्नाइटिंग बंगाल्स इंडस्ट्रियल फॉर्च्यून' कार्यक्रम में बोलते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि सिंगूर से टाटा मोटर्स के जाने के बाद देशभर में यह संदेश गया था कि पश्चिम बंगाल उद्योगों के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार इस धारणा को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है और टाटा समूह की वापसी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। भट्टाचार्य ने कहा कि टाटा वापस आएंगे। अगर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नहीं, तो किसी अन्य उद्योग में निवेश करेंगे। यह हमारे लिए जिम्मेदारी भी है और चुनौती भी। उनकी वापसी से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सिंगूर की जमीन की स्थिति पहले जैसी नहीं रही है, लेकिन सरकार टाटा समूह के साथ लगातार संपर्क में है। यदि सिंगूर में परियोजना स्थापित करना संभव नहीं हुआ तो राज्य के किसी अन्य हिस्से में निवेश की संभावनाएं तलाश की जाएंगी। बता दें कि साल 2008 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के बाद टाटा मोटर्स को अपनी नैनो कार परियोजना सिंगूर से हटाकर गुजरात के सानंद ले जानी पड़ी थी। उस समय कंपनी सिंगूर परियोजना में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर चुकी थी। बाद में एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। भट्टाचार्य ने उद्योगपतियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में व्यापारिक गतिविधियों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति पार्टी का नाम लेकर कारखानों में दबाव बनाने या अनुचित मांगें करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अगले 1,000 दिनों में राज्य का कारोबारी माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। बीजेपी सरकार उद्योग, निवेश और रोजगार को प्राथमिकता देते हुए पश्चिम बंगाल को फिर से देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में शामिल करने की दिशा में काम करेगी।

'देश की सुरक्षा के लिए हमने दे दी अपनी जमीन'

बंगाल बॉर्डर के गांव वालों ने पेश की देशभक्ति की नई मिसाल

- भारत-बांग्लादेश सीमा पर लंबे समय से बाड़ लगाने की योजना अटकी हुई थी
- राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर 142.79 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंप दी
- 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है
- किसानों और सीमा के पास रहने वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगी

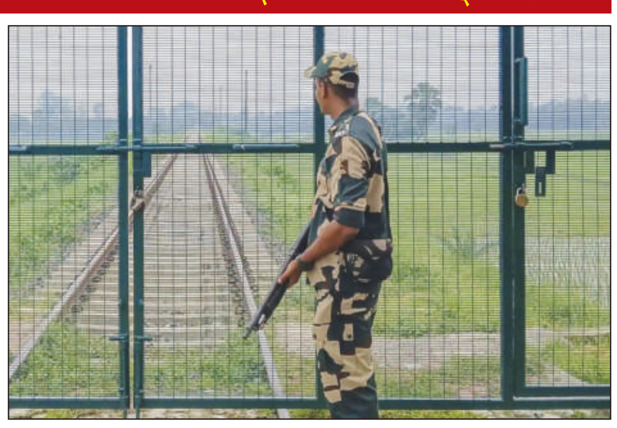

निज संवाददाता : भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के कुछ ग्रामीणों ने ऐसा कदम उठाया है, जिसने सीमा सुरक्षा और देशभक्ति को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। सतग्राम मानाबाड़ी इलाके के तीन ग्रामीणों ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन स्वेच्छा से दान कर दी। उनका कहना है कि सालों से बिना फेंसिंग के गांव के लोग घुसपैठ, चोरी और तस्करी की समस्या झेलते रहे हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि कांटेदार तार लगने के बाद गांव और देश दोनों सुरक्षित होंगे।''मैंने अपनी जमीन देश की सुरक्षा के लिए दे दी'' यह कहना है विकास राय का, जिन्होंने 20 डिसमिल जमीन सीमा बाड़बंदी के लिए दे दी। विकास कहते हैं कि गांव के लोगों ने डर और असुरक्षा के बीच लंबा समय बिताया है। रात के अंधेरे में सीमा पार से लोग आते थे, मवेशी चोरी होते थे और खेतों को नुकसान पहुंचाया जाता था। उन्होंने कहा-हमने जमीन इसलिए दी ताकि हमारा गांव सुरक्षित रहे और देश भी सुरक्षित रहे। पहले यहां कोई फेंसिंग नहीं थी। बांग्लादेशी घुसपैठिए रात में आ जाते थे। चोरी और घुसपैठ आम बात थी। अब अगर फेंसिंग हो जाएगी तो गांव के लोग चैन से रह पाएंगे। भारत-बांग्लादेश सीमा पर लंबे समय से बाड़ लगाने की योजना अटकी हुई थी। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस दिशा में तेजी दिखाई गई। सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को जमीन सौंपने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी। 28 मई को राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर 142.79 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंप दी। यह उस बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तस्करी और अवैध आवाजाही की रही है। हृदय बर्मन, जो जमीन दान करने वाले परिवार से जुड़े हैं, कहते हैं कि बिना तारबंदी के गांव के लोग लगातार खतरे में रहते थे। गांव वालों ने कहा-यह सिर्फ गांव की सुरक्षा का मामला नहीं है, यह पूरे भारत की सुरक्षा का सवाल है। यहां चोरी और तस्करी बड़े पैमाने पर होती थी। अगर फेंसिंग पूरी हो गई तो किसानों और सीमा के पास रहने वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगी। जमीन देने वाले ग्रामीणों को अभी मुआवजा नहीं मिला है। बिकाश राय ने बताया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही मुआवजे की राशि मिल जाएगी। सीमा पर रहने वाले लोगों की इस पहल ने यह दिखा दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सरकारों और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि आम नागरिक भी इसके लिए बड़ा त्याग करने को तैयार रहते हैं। कूचबिहार के इन ग्रामीणों का कदम अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

राज्य में 1 अगस्त से शुरू होगी जनगणना

निज संवाददाता : जनगणना को लेकर हुई मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में 1 अगस्त से जनगणना शुरू होगी। 15 अगस्त तक सेल्फ-एन्यूमरेशन सिस्टम (स्व-गणना प्रणाली) लागू रहेगा। यह काम फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली बार है जब जनगणना डिजिटल तरीके से होगी। शुभेंदु ने साफ कहा-जनगणना एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफिक्स बदल गए हैं। याद रखें, इसका राजनीति या जाति से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा और कहा-पिछली सरकार के घमंड की वजह से हम पीछे रह गए। पहले से ही संकेत थे कि अगस्त में जनगणना हो सकती है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को बैठक के बाद जनगणना का ऐलान किया। प्रोसेस का ऐलान करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 1 अगस्त से जनगणना शुरू होगी। लोग 15 अगस्त तक खुद से गिनती करेंगे। पूरे प्रोसेस में जनता को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जा रहा है। पूरे देश में जो नंबर लॉन्च होगा, वह 1855 है। एक और लैंडलाइन नंबर लॉन्च किया जाएगा। वह है- 033-2335 9503। वेबसाइट लॉन्च हो गई है- www.westbengal.census.gov.in। जनगणना को लेकर बहुत से लोगों के मन में कई सवाल और डर हैं। इस दिन मुख्यमंत्री ने इस बारे में कहा-जनगणना एक संवैधानिक ज़िम्मेदारी है। बंगाल में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। पिछली सरकार ने उसके बाद जनगणना नहीं करवाई। उस समय के मुख्य सचिव ने अपनी मंज़ूरी नहीं दी थी। लेकिन, बंगाल के मौजूदा हालात, घुसपैठियों की वजह से जिस तरह आबादी बदली है, उसकी वजह से जनगणना ज़रूरी है। इस दिन घुसपैठियों का ज़िक्र करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा-आप देख सकते हैं कि कई बांग्लादेशी जनगणना के डर से भाग रहे हैं। फिलहाल, जो लोग होल्डिंग सेंटर में हैं, उनमें से कोई भी ज़रूरी कागज़ात नहीं दिखा पाएगा। हालांकि, शुभेंदु ने समझाया कि इस देश, बंगाल के नागरिकों को जनगणना को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा-जनगणना का राजनीति या जाति से कोई लेना-देना नहीं है। यह हमारी ज़िम्मेदारी है।

बंगाल में भाजपा की जीत के बाद कॉलेजों में बढ़ रहा आरएसएस से जुड़े संगठनों का दायरा

निज संवाददाता : बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद यहां की राजनीति में आए बड़े बदलाव का असर अब राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में भी साफ दिखाई देने लगा है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत के कुछ ही हफ्तों बाद आरएसएस से जुड़े छात्र और शिक्षक संगठनों ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अपनी सक्रियता तेजी से बढ़ा दी है। कभी वामपंथ और तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाले कैंपस अब धीरे-धीरे नए वैचारिक बदलाव की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। उत्तर बंगाल के कॉलेज कैंटीन से लेकर कोलकाता के विश्वविद्यालय परिसरों तक माहौल बदलता दिख रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), जो लंबे समय तक बंगाल की छात्र राजनीति में सीमित प्रभाव रखती थी, अब तेजी से विस्तार कर रही है। संगठन का दावा है कि चुनाव से पहले उसकी मौजूदगी करीब 96 कॉलेजों तक थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। एबीवीपी नेताओं के अनुसार, बड़ी संख्या में छात्र संगठन से जुड़ने के लिए संपर्क कर रहे हैं। कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नए यूनिट बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। एबीवीपी फिलहाल सीधे कैंपस कमेटियां घोषित करने के बजाय छात्रों को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और डिजिटल नेटवर्क का सहारा ले रही है। संगठन पहले इच्छुक छात्रों की जांच और वैचारिक समझ को परख रहा है। सूत्रों के मुताबिक, हाल के दिनों में टीएमसी छात्र परिषद (टीएमसीपी और एसएफआई से जुड़े कई छात्र भी एबीवीपी के संपर्क में आए हैं। सिर्फ छात्र संगठन ही नहीं, बल्कि शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच भी आरआरएस समर्थित संगठनों की सक्रियता बढ़ी है। भारतीय शिक्षण मंडल और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (एबीआरएसएम) का दावा है कि उनकी सदस्यता में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। एबीआरएसएम के पदाधिकारियों के अनुसार, राज्य के कई जिलों में अब शिक्षक और कर्मचारी बड़ी संख्या में संगठन से जुड़ना चाहते हैं। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ संगठनात्मक विस्तार नहीं बल्कि बंगाल की शिक्षा और छात्र राजनीति में बड़े वैचारिक बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं। दशकों तक वामपंथी विचारधारा का गढ़ रहे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अब राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति की चर्चा बढ़ने लगी है। आरएसएस से जुड़े रणनीतिकार लंबे समय से मानते रहे हैं कि बंगाल में स्थायी राजनीतिक प्रभाव के लिए शिक्षा संस्थानों में मजबूत पकड़ बनाना जरूरी है। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का तात्कालिक असर है और वर्षों से बने संस्थागत प्रभाव को इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कैंपस का माहौल पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से बदल रहा है।

शुभेंदु सरकार की 'डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट' नीति का असर

बंगाल बॉर्डर पर लौटने के लिए अवैध घुसपैठियों की उमड़ी भीड़

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार की डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट नीति का असर होने लगा है। इसके तहत बंगाल से अवैध घुसपैठियों को डिपोर्ट (देश-निकाला) करने का आदेश देने के बाद हलचल मच गई है। बंगाल में बसे अवैध बांग्लादेशियों में चिंता फैल गई है। इधर गिरफ्तारी और कार्रवाई से बचने के लिए अवैध बांग्लादेशियों ने पलायन शुरू कर दिया है। आलम यह कि स्वरूपनगर में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास अवैध अप्रवासियों का मजमा लग गया है। वे अपने सामान के बाद बांग्लादेशी सीमा पर एकत्र हो गए। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए फोर्स बढ़ानी पड़ी। बीएसएस और सतर्क हो गई है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस विभाग और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दूसरे देशों से आए गिरफ्तार किए गए अवैध घुसपैठियों को अदालतों में पेश करने के बजाय सीधे निकटतम सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सीमा चौकियों पर भेज दें। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना ज़िले में हकीमपुर सीमा क्षेत्र पर लोगों की भीड़ देखी गई। माना जा रहा है कि ये लोग बांग्लादेश लौटने के लिए वहां जमा हुए हैं। यह सब तब हो रहा है जब राज्य सरकार कथित अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के

खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। इससे पहले भी इसी तरह के दृश्य तब देखने को मिले थे, जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) प्रक्रिया शुरू हुई थी। स्वरूपनगर बॉर्डर पर मौजूद लोगों ने कहा कि हमें लगा था कि टीएमसी जीतेगी, लेकिन बीजेपी जीत गई है इसीलिए हम यहां से जा रहे हैं। इससे पहले, मुख्यमंत्री शुभेंदु ने कहा था कि अवैध घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंपने की व्यवस्था पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने पुलिस और आरपीएफ अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उन्हें निर्देश दिया कि वे गिरफ्तार किए गए अवैध घुसपैठियों को अदालतों में पेश करने के बजाय निकटतम बीएसएफ सीमा चौकियों (बीओपीएश) पर भेज दें। अब से, यदि कोई अवैध घुसपैठिया हावड़ा स्टेशन पर या कहीं और गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और सीधे बीएसएफ बीओपीएस पर भेज दिया जाएगा या तो बनगांव उप-मंडल में बेनापोल-पेट्रापोल सीमा चौकी पर, या बशीरहाट में स्थित चौकी पर। ये दोनों ही उत्तरी 24 परगना जिले में हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अवैध बांग्लादेशियों का पता लगाओ-हटाओ और निर्वासित करो। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट नीति पर काम कर रही है। इस नीति का वादा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव-पूर्व अभियानों के दौरान किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनका कार्यालय गिरफ्तार किए गए और बीएसएफ चौकियों पर भेजे गए अवैध घुसपैठियों की संख्या का साप्ताहिक ब्योरा रखेगा। हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के मुख्य चुनावी मुद्दों में से एक न केवल अवैध घुसपैठ को रोकना था, बल्कि राज्य को उन अवैध घुसपैठियों से मुक्त कराना भी था, जो कथित तौर पर जाली भारतीय पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके वहां रह रहे हैं। मालदा राज्य का पहला ऐसा ज़िला बन गया है, जहां अवैध विदेशी नागरिकों के लिए एक होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस सेंटर में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा जाना शुरू हो गया है।

बंगाल में भी लागू होगी 'पीएम श्री योजना'

छात्रों के समग्र विकास के लिए हर ब्लॉक में चुने जाएंगे मॉडल स्कूल

निज संवाददाता : बंगाल में भी पीएम श्री मॉडल स्कूल शुरू होने जा रहा है। दरअसल राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की संभावना बन गई थी। बीते 15 मई को दिल्ली में केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय और पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षा विभाग के बीच एक एमओयू साइन हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पश्चिम बंगाल में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। अधिकारी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।स्कूल शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) को 2022-23 से शुरू किया था। 2027 तक पूरे राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के ज़रिए 14 हज़ार से ज़्यादा स्कूलों को इस पीएम श्री प्रोजेक्ट के तहत लाने का काम शुरू हो गया है। इसका लक्ष्य राज्य के हर ब्लॉक में कम से कम एक स्कूल को चुनकर उसे इस प्रोजेक्ट में शामिल करना है। ऐसे में उस स्कूल का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पढ़ाने के तरीके तक, स्कूल हर जगह मॉडल के तौर पर जाने जाएंगे। वे स्कूल आस-पास के स्कूलों के छात्रों के समावेशी विकास में भी मदद करेंगे। केंद्र सरकार ने विकास क्षेत्र के लिए 27 हजार करोड़ रुपये से ज़्यादा दिए हैं। स्कूलों को मॉडल बनाने के लिए कुल रकम का 60 फीसदी केंद्र सरकार देगी और 40 फीसदी राज्य सरकार देगी। लेकिन शर्त यह है कि मॉडल स्कूल के

नाम के आगे पीएम श्री जोड़ा जाएगा। यहीं पर पश्चिम बंगाल की पूर्व ममता बनर्जी सरकार ने एतराज़ जताया था। विभाग के सूत्रों के मुताबिक, उस समय राज्य सरकार का तर्क था कि राज्य भी इस प्रोजेक्ट में पार्टनर है। शिक्षा संविधान की संयुक्त सूची में है। इसलिए स्कूल के नाम के आगे पीएम जोड़ना सही नहीं है। लिहाजा, उस समय की राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए राज़ी नहीं हुई थी।लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद यह समझा गया कि इस प्रोजेक्ट में शामिल होना बस कुछ ही समय की बात है। पिछले दिनों केंद्र और राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग के अधिकारी दिल्ली में मौजूद थे। यहीं पर इस प्रोजेक्ट में पश्चिम बंगाल का नाम जोड़ा गया। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में राज्य के हर जिले के हर ब्लॉक में कम से कम एक स्कूल चुनने का काम शुरू हो गया है। इसके बाद उन स्कूलों को पीएम श्री मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। ऐसे में स्कूल के समावेशी विकास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाने के तरीकों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। राज्य में पहले से ही कई केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों को ये मॉडल स्कूल बनाया जा चुका है। अब राज्य सरकार सरकारी और सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कूलों को भी मॉडल बनाने का काम शुरू करेगी। बंगाली टीचर्स एंड एजुकेशन वर्कर्स एसोसिएशन के महासचिव स्वपन मंडल ने कहा-हालांकि केरल की पिछली लेफ्ट सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मान लिया था, लेकिन हमारे राज्य की तृणमूल सरकार ने इसे नहीं माना। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों के फायदे के लिए यह प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जाना चाहिए।

सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों के लिए शुरू किए गए स्पेशल आई-कार्ड

दलाली पर रोक लगाने के लिए शुभेंदु सरकार का नया कदम

निज संवाददाता : राज्य के सरकारी अस्पतालों में दलाली पर रोक लगाने के लिए शुभेंदु सरकार नया कदम उठाने जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार अस्पताल के कर्मचारियों के लिए खास कार्ड लाने जा रही है। लैब में काम करने वालों के आई-कार्ड ऑरेंज रंग के होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के पर्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के ब्लैक, नर्स के ब्राउन, सिक्योरिटी स्टाफ के मैरून और हॉस्पिटल के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के ग्रीन रंग के कार्ड हैं। ऐसे अलग-अलग रंग के आई-कार्ड सबके लिए बनाए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि सरकारी अस्पतालों में दलालों और घुसपैठ को रोकने के लिए सभी के लिए अलग आई-कार्ड बनाया जाएगा। उस पहचान पत्र के बिना कोई भी हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर पाएगा। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें साफ-साफ बताया गया है कि किस रंग का आई-कार्ड किसके लिए है। यह निर्देश एसएसकेएम,

आरजी कर मेडिकल कॉलेज, एनआरएस मेडिकल कॉलेज, कोलकाता मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज, शंभूनाथ पंडित हॉस्पिटल, कोलकाता पुलिस हॉस्पिटल समेत सभी सरकारी अस्पतालों को भेजा गया है। यह तय किया गया है कि हॉस्पिटल की हर बिल्डिंग के लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। वह इस प्रोजेक्ट के सभी काम को कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करेगा। प्रोजेक्ट को आसानी से चलाने के लिए, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन और एक ऑफिस डेस्क का इंतज़ाम करना होगा। हर हॉस्पिटल अथॉरिटी को आईटी स्टाफ़ (वेबेल) के अपॉइंटमेंट का इंतज़ाम करना होगा, जो टेक्निकल दिक्कतों को ठीक करने के लिए मौजूद रहेंगे। आईडी कार्ड के रजिस्ट्रेशन के दौरान भीड़ नियंत्रण और आसान मैनेजमेंट के लिए कुछ वॉलंटियर्स का इंतज़ाम करना होगा। कर्मचारियों को कई कैटेगरी में बांटा गया है, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़, पैरा-मेडिकल, जीडीए अन्य (ड्राइवर सहित)। हॉस्पिटल में झाड़ू लगाने वाले सफ़ाई कर्मचारियों को भी अब से खास पीले आईडी कार्ड पहनने होंगे। जो लोग आउटसोर्स काम करते हैं, उनके लिए नीले आई-कार्ड तय किए गए हैं।

शुभेंदु ने किया 'अपनी सरकार को बताएं' कार्यक्रम का ऐलान

♦ ममता युग का 'मुख्यमंत्री को बताएं' प्रोग्राम अब नए रूप में

निज संवाददाता : तृणमूल के ज़माने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री को बताएं प्रोग्राम शुरू किया था। इस बार वह प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। अब इस प्रोग्राम का नया नाम अपनी सरकार को बताएं है। नादिया में प्रशासनिक बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया। पुराना फ़ोन नंबर अब नहीं रहेगा। नया फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा। उसका भी आज ऐलान किया गया।

मुख्यमंत्री को बताएं प्रोग्राम राज्य सरकार ने तृणमूल के ज़माने में शुरू किया था। बताया जाता है कि यह काम तब शुरू हुआ जब आम लोगों ने उस समय की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी परेशानियां, शिकायतें और मांगें बताईं। उस समय लोगों ने भी अपनी परेशानियां बतानी शुरू कर दीं। अपनी दीदी को बताएं प्रोग्राम भी उस समय तृणमूल ने शुरू किया था। फ़ोन नंबर भी दिया गया था। आरोप है कि तृणमूल की वोट बनाने वाली संस्था एआईपीएसी के ऑफ़िस का फ़ोन नंबर दिया गया था। दोनों ही मामलों में लोगों की बातें उस वोट बनाने वाली संस्था के पास गईं। बाद में आरोप है कि उन फ़ोन नंबरों पर कॉल करने के बाद भी बात नहीं हो पाई। राज्य में बीजेपी सत्ता में आ गई है। तृणमूल के समय में सरकारी कामों का जो स्ट्रक्चर था, वह भी बदल रहा है। सरकार की तरफ से कई नई एक्टिविटी शुरू की जा रही हैं। इस बार मुख्यमंत्री को बताएं प्रोग्राम भी बंद कर दिया गया है। अगले हफ्ते से नए नाम से एक नया सरकारी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। आम लोग अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकेंगे। इस नए प्रोजेक्ट का नाम अपनी सरकार बताएं है। मुख्यमंत्री ने आज कल्याणी से एक बड़ा ऐलान किया। यह प्रोग्राम अगले हफ्ते से शुरू किया जाएगा। बातचीत के लिए एक नए नंबर का भी ऐलान किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का नाम तय करने की जिम्मेदारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य को दी गई थी। उन्होंने ही यह नाम दिया।

'फिर से जाग उठी हैं कोलकाता लौटने की उम्मीदें'

निज संवाददाता : बांग्लादेश में जन्मीं और अब दिल्ली में निर्वासित जीवन बिता रहीं लेखिका तसलीमा नसरीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन से कोलकाता लौटने की उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। नवंबर 2007 में उन्हें इसी शहर से बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने बताया कि तब से उन्हें इस शहर में लौटने की अनुमति नहीं मिली है। काफी उत्साहित नज़र आ रहीं तसलीमा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब हालात बदल सकते हैं। मैं हमेशा से कोलकाता लौटना चाहती थी, लेकिन यह मेरी एक अधूरी ख्वाहिश ही बनी रही, क्योंकि न तो वाम मोर्चा सरकार ने और न ही तृणमूल सरकार ने इसकी अनुमति दी। इससे पहले, मेरे लिखी गई एक मेगा सीरियल को भी तृणमूल सरकार के निर्देशों के बाद बंद करना पड़ा था। तसलीमा नसरीन ने कहा कि अगर मेरे लिए कोलकाता में रहना संभव हुआ, तो मैं निश्चित रूप से वहीं रहूंगी। अगस्त 1994 में बांग्लादेश से निकाले जाने के बाद, कोलकाता ही मेरा घर बन गया था, क्योंकि यहां मुझे उसी बंगाली संस्कृति का अनुभव करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं यूरोप छोड़कर कोलकाता आई थी। लेखिका तसलीमा ने कहा कि मैं कोलकाता जाकर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहती हूं, क्योंकि इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। मैं कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भी शामिल होना चाहती हूं। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने भारत के कई हिस्सों की यात्रा की है और हाल ही में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केरल भी गई थीं। अगर राज्य सरकार मुझे कोलकाता आने की अनुमति देती है, तो मैं उनकी बहुत आभारी रहूंगी। लेखिका तसलीमा नसरीन ने कहा कि वह नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखकर कोलकाता लौटने की अनुमति देने का अनुरोध करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले

बंगाल में सत्ता परिवर्तन से उत्साहित हैं तसलीमा नसरीन

दो दशकों से, मैं कोलकाता में बसने का सपना संजोए हुए हूं और अब मैं वहां जाकर बसने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अगर राज्य सरकार मेरी मदद करती है, तो मैं कोलकाता में ही रहूंगी। भाजपा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने पिछले साल राज्यसभा में उनके इस मुद्दे को उठाया था और गृह मंत्रालय से कोलकाता में उनके रहने की व्यवस्था करने का आग्रह किया था। तसलीमा ने बताया कि कई संगठनों ने कोलकाता आने के संबंध में उनसे संपर्क किया है, लेकिन उन्हें अभी भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि वह वास्तव में कब इस शहर की यात्रा कर पाएंगी। जुलाई में, उन्हें एक बंगाली सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका जाना था। लेखिका ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो अभी निर्वासन में हैं को बांग्लादेश लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। भले ही हसीना ने खुद कभी यह नहीं चाहा था कि लेखिका देश लौटें। उन्होंने यह भी महसूस किया कि अवामी लीग पर लगा प्रतिबंध तत्काल हटा दिया जाना चाहिए।

शुभेंदु अधिकारी ने चिकन नेक की जमीन और हाइवे केंद्र सरकार को दिया

पूर्ववर्ती ममता सरकार के पास यह प्रस्ताव एक साल से लंबित था

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सिलिगुड़ी कॉरिडोर यानी नॉर्थ-ईस्ट के चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन और एनएच-10 और एनएच-110 के सात हिस्सों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और एनएचआईडीसीएल को सौंपने की मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव पिछली ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के पास एक साल से लंबित था, जिसे शुभेंदु सरकार ने शपथ लेने के 10 दिनों के भीतर क्लियर कर दिया।

2017 में चीन के साथ डोकलाम गतिरोध के बाद भारत सरकार ने देश की सीमाओं पर इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में तेजी दिखाई। एक्सपर्टस ने चिकन नेक की सुरक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्टर बढ़ाने पर जोर दिया। मॉनसून के दौरान एनएच-10 पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक जाम और जमीन धंसने की समस्या होती हैं। इन हालातों में सिक्किम में सप्लाई रुक जाती है और पूरा राज्य संवेदनशील जोन में पहुंच जाता है। अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ किया गया, तब भारत की चिंता और बढ़ गई। डॉ. मुहम्मद यूनुस के चिकन नेक को लेकर दिए गए बयानों से केंद्र सरकार अलर्ट मोड में चली गई। 2025 में विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन पड़ोसी देश बांग्लादेश में

चिकन नेक के बारे में जानिए

* केंद्र सरकार को दिए नेशनल हाईवे के सात हिस्सों में से पांच चिकन नेक से होकर गुजरते हैं।
* 60 किलोमीटर लंबा इलाके का सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 20-22 किलोमीटर चौड़ा है।
* इसके बॉर्डर तीन देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जुड़ते हैं।
* सिलिगुड़ी कॉरिडोर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि चिकन नेक कॉरिडोर में किसी तरह की रुकावट आई तो नॉर्थ-ईस्ट के 8 राज्यों का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से कट सकता है।
* इस कॉरिडोर के एक छोर पर सिक्किम है, जिससे चीन की सीमा जुड़ती है। नॉर्थ-ईस्ट में डिफेंस के साजो-सामान पहुंचाने, बिजनेस, टूरिजम के लिए भी यह बेहद महत्वपूर्ण है।

लालमोनिरहाट एयरबेस पर हवाई पट्टी बना रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत की सीमा के पास बनने वाले एयरफील्ड को विकसित करने में पाकिस्तान भी बांग्लादेश की मदद कर रहा है। लालमोनिरहाट एयरबेस भारत के पश्चिम बंगाल और मेघालय से मात्र 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सिलिगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत का चिकन नेक इसे 135 किमी के दायरे में आता है। बाद में बांग्लादेश की सफाई आई कि लालमोनिरहाट एयरबेस का उपयोग सैन्य गतिविधियों के लिए नहीं होगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार भी चीन और पाकिस्तान के साथ सामरिक चुनौती पेश कर रहा है। गौरतलब है कि बंगाल के राजनीतिक मोर्चे पर चिकन कॉरिडोर को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच तलवारें खिंची रहीं।

बीजेपी हमेशा ममता बनर्जी सरकार पर घुसपैठियों को शह देकर उत्तर बंगाल की डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाती रही। चुनावों में भी बीजेपी ने सिलिगुड़ी कॉरिडर की सुरक्षा को घुसपैठियों के मुद्दे से जोड़ा। ममता बनर्जी लगातार यह कहती रहीं कि बॉर्डर पर सुरक्षा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहीं बीजेपी ने दावा किया कि बंगाल में डबल इंजन सरकार ही चिकन नेक को सुरक्षित रख सकती है। पश्चिम बंगाल में भारी जीत के बाद बीजेपी सरकार ने शुरुआती फैसले में बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए 45 दिनों के भीतर जमीन देने का आदेश जारी किया। फिर नॉर्थ-ईस्ट के चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन और हाइवे के 7 हिस्से एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल को सौंपने की सहमति दे दी।

तृणमूल सरकार गिरने की मांगी थी मन्नत

पूरी होने पर बीजेपी कार्यकर्ता ने 10 किमी दंड काटकर मंदिर में की पूजा

निज संवाददाता : उन्होंने मन्नत मांगी थी। वह पूरी हुई। आखिरकार, अपने मन्नत के मुताबिक, सुंदरबन के बीजेपी कार्यकर्ता ने मंदिर जाकर 10 किमी लंबी सड़क पारकर पूजा-अर्चना की। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, सुजीत मंडल सुंदरबन के बासंती ब्लॉक में बामचंद्रखाली पंचायत के चारपारा गांव के रहने वाले हैं। उनकी स्ट्रीट फूड की दुकान है। जैसे ही बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, बैशाख के पहले दिन पार्टी के एक वफ़ादार कार्यकर्ता सुजीत अपने घर से दस किमी दूर मोकाम्बेरिया में बाराकाचारी शिव मंदिर गए और मन्नत मांगी कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी अकेले दम पर सत्ता में आई। 9

मई को शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सुजीत और उनके परिवार और पड़ोसी बहुत खुश हुए। सुजीत ने देर नहीं की क्योंकि उनका सपना सच हो गया था। वे रविवार रात 8:30 बजे अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ घर से निकले। 10 किमी का लंबा सफ़र तय करने के बाद, वह सोमवार सुबह 2:45 बजे बाराकाचारी मंदिर पहुंचे। वहां, उन्होंने सुबह स्नान किया और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए 108 कमल की माला, फल और दूब से पूजा की। सुजीत ने कहा-मैं 10 साल से ज़्यादा समय से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं। 2023 के पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के बेईमान लोगों की वजह से कोई भी ग्राम सभा का चुनाव नहीं लड़ पाया। उस समय मेरी पत्नी टुम्पा मंडल ग्राम सभा के लिए बीजेपी की उम्मीदवार बनीं। बाद में मुझे तरह-तरह से धमकाया गया। कहा गया कि दुकानों और घरों में तोड़-फोड़ की जाएगी। आतंकवाद किया जाएगा। लगातार मिल रही धमकियों से मैं परेशान हो गया। आखिर में मेरी पत्नी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। मुझे इस बात का गुस्सा था। जिसे मैं ज़ाहिर नहीं कर सका। मैंने बाराकचारी मंदिर में मन्नत मांगी कि 2026 के चुनाव में हरमदों को रोकूंगा और बीजेपी सत्ता में आएगी।

एसआईआर के तहत जारी जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों का फिर से सत्यापन करेगा कोलकाता नगर निगम

सत्ता बदलते ही पुराने फैसलों और डॉक्यूमेंट्स की जांच की प्रक्रिया शुरू

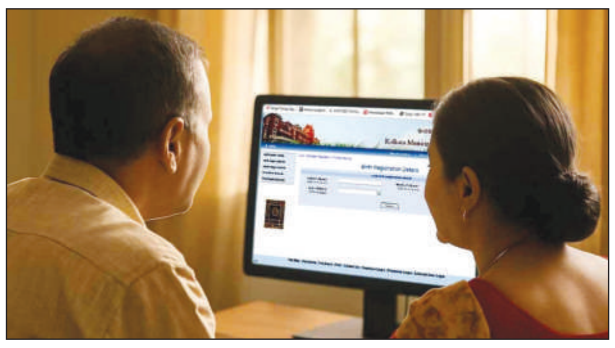

निज संवाददाता : राज्य सरकार की तरफ से मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान जारी किए गए जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट को फिर से वेरिफाई करने का फैसला किया गया है। राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद, प्रशासनिक स्तर पर कई पुराने फैसलों और डॉक्यूमेंट्स की जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इसी सिलसिले में कोलकाता नगर निगम द्वारा जारी किए गए जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट प्रशासन के ध्यान में आए हैं। हालांकि अगले साल दिसंबर तक कोलकाता नगर निगम में तृणमूल के नेतृत्व वाला बोर्ड सत्ता में है, लेकिन मौजूदा हालात में नगर निगम के कई फैसलों को लेकर सत्ताधारी खेमे में बेचैनी है।

प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि एसआईआर प्रोसेस के दौरान पिछले साल नवंबर और दिसंबर में कोलकाता नगर निगम में जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए बड़ी संख्या में एप्लीकेशन जमा किए गए थे। आरोप है कि उस समय कई सर्टिफिकेट जल्दबाजी में जारी किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक, उस समय की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को आवेदकों की मांगों के अनुसार सर्टिफिकेट जल्दी जारी करने का निर्देश दिया था। इसी वजह से, कोलकाता नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग अब यह देख रहा है कि जल्दबाजी में जारी किए गए कुछ सर्टिफिकेट में कोई फैक्ट्स की गलती, गड़बड़ी या गड़बड़ी तो नहीं है। प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि वोटर लिस्ट में बदलाव के दौरान इस्तेमाल किए गए डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा अहमियत से जांच हो सकती है। गौरतलब है कि राज्य की अलग-अलग म्युनिसिपैलिटी और पंचायत इलाकों में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग का एक सेंट्रल डिजिटल पोर्टल 2021 में लॉन्च किया गया था।

उस पोर्टल के ज़रिए जानकारी अपलोड की जाती है और डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। हालांकि, खबर है कि पोर्टल की कई सर्विस बुधवार से अचानक थोड़ी बंद कर दी गई हैं। फिलहाल, सिर्फ़ नए जन्म या मृत्यु के मामले में जानकारी रजिस्टर की जा रही है और उन आवेदकों को डिजिटल सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। लेकिन पुराने जन्म या मृत्यु रिकॉर्ड को फिर से रजिस्टर करने, पिछली घटनाओं के डिजिटल सर्टिफिकेट बनाने या खोए हुए सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी पाने की सर्विस फिलहाल रोक दी गई हैं। ऐसे भी आरोप लगे हैं कि पोर्टल से ज़रूरी ऑप्शन हटा दिए गए हैं। प्रसासनिक सूत्रों का दावा है कि एसआईआर के दौरान जारी सभी जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट को फिर से वेरिफाई करने के फैसले की वजह से पुरानी एंट्री से जुड़ी सर्विस कुछ समय के लिए रोक दी गई हैं। हालांकि, इस बारे में अभी तक स्वास्थ्य विभाग या कोलकाता नगर निगम की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है।

पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात की वजह से सरकारी अस्पतालों में सलाइन की कमी

निज संवाददाता : पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात की वजह से पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में सलाइन की कमी हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में एक नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात की वजह से कई दवाओं और इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कमी हो गई है। पश्चिम एशिया में युद्ध, यानी इज़राइल, ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा लड़ाई की वजह से हालात गरमा गए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध की वजह से इंटरनेशनल मार्केट से आने वाले कई केमिकल इंग्रीडिएंट्स, मेडिकल इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और पैकेजिंग मटीरियल में रुकावट आ रही है। युद्ध के हालात में जहाज़ के किराए और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से सप्लाई बनाए रखना मुश्किल हो गया है। जिसकी वजह से पैरासिटामोल टैबलेट, 100 एमएल सलाइन, पैंटोप्राजोल टैबलेट, ओआरएस, मेटफॉर्मिन टैबलेट, टेल्मिसर्टन टैबलेट, डिस्पोजेबल सिरिंज की सप्लाई में कमी हो गई है। इस मुश्किल से निपटने के लिए, सभी संबंधित अस्पतालों और ज़िला अस्पतालों के अधिकारियों को बताया गया है कि इन इंग्रीडिएंट्स को नॉन-कैटलॉग आइटम या नॉन-कैटलॉग आइटम के तौर पर खरीदना होगा। यानी ये चीज़ें सप्लाई लिस्ट में नहीं मिलेंगी। गौर करने वाली बात है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से होर्मुज लंबे समय से ब्लॉक है। ईरान ने होर्मुज के ज़रिए सामान का ट्रांसपोर्ट रोक दिया है, जबकि बदले में अमेरिका ने ईरानी पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया है। जिसकी वजह से ग्लोबल एनर्जी संकट के अलावा भारत पर भी इसका गंभीर असर पड़ा है। सिर्फ़ फ्यूल ही नहीं, बल्कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग मटीरियल और रोज़ाना की कई ज़रूरतों की चीज़ें भी महंगी हो गई हैं या उनके दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। इसका हेल्थ सेक्टर पर गंभीर असर पड़ा है।

कड़ी कर दी गई है कोलकाता नगर निगम की सेंट्रल बिल्डिंग की सुरक्षा

बिना इजाज़त के एक भी फ़ाइल दफ़्तर के बाहर नहीं जा सकती

निज संवाददाता : कोलकाता नगर निगम की सेंट्रल बिल्डिंग की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एंट्री और एग्जिट (प्रवेश और निकास) पॉइंट पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। दफ्तर से एक भी फाइल बाहर नहीं ले जाने दी जाएगी। कई बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया है कि कोलकाता नगर निगम के ज़रूरी डॉक्यूमेंट और फाइलें नष्ट कर दी गई हैं। उस संदर्भ में, कोलकाता नगर निगम कमिश्नर स्मिता पांडे ने सेंट्रल बिल्डिंग की सुरक्षा और मजबूत करने का आदेश दिया है। ऐसा नगर निगम सूत्रों ने बताया है।नए निर्देशों के अनुसार, कोलकाता नगर निगम की सेंट्रल बिल्डिंग के सभी छोटे-बड़े एंट्री और एग्जिट (प्रवेश और निकास) पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही, हर गेट पर ज़रूरत के हिसाब से अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड तैनात करने का भी आदेश दिया गया है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना इजाज़त के कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट बिल्डिंग से बाहर नहीं ले जा सकेगा। निर्देशों में यह पक्का करने को कहा गया है कि किसी भी हालत में ज़रूरी फाइलें ऑफिस से बाहर न जाएं।वैसे, कुछ दिन पहले, वार्ड नंबर 45 के बीजेपी पार्षद संतोष पाठक ने शिकायत की थी कि कोलकाता नगर निगम में कई जगहों पर फाइलें बैग में पड़ी हैं। वह नगर सचिव किशोर कुमार विश्वास को नगर निगम बिल्डिंग के अलग-अलग हिस्सों में ले गए। उस समय आरोप था कि बिल्डिंग में कई जगहों पर बोरियों में बंद फाइलें पड़ी हुई थीं। उन्होंने सवाल उठाए कि वहां किस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स रखे थे, उन्हें बोरियों में क्यों भरा गया था और उन्हें कहां ले जाने की योजना थी।बीजेपी विधायक और वार्ड नंबर 50 के पार्षद सजल घोष और मीनादेवी पुरोहित ने भी आरोप लगाया कि तृणमूल नगर निगम के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हटाने की कोशिश कर रही है। उनका दावा है कि यह सब पिछले 15 सालों में तृणमूल के नगर निगम बोर्ड चलाने के दौरान हुए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि इस आरोप के समर्थन में अभी तक कोई ऑफिशियल सबूत सामने नहीं आया है।नगर निगम सचिव ने मामले को देखने और नगर निगम कमिश्नर से इस पर चर्चा करने का भरोसा दिया। नगर निगम के एक सूत्र ने दावा किया कि सुरक्षा को लेकर यह नया आदेश उसी रिव्यू के बाद जारी किया गया है। हालांकि, नगर निगम प्रशासन का कोई भी अधिकारी इस मामले पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहना चाहता। माना जा रहा है कि नया आदेश लागू होने के बाद, संबंधित विभाग की मंज़ूरी या नगर निगम प्रशासन के बड़े अधिकारियों के लिखित आदेश के बिना कोलकाता नगर निगम की सेंट्रल बिल्डिंग से कोई भी फाइल बाहर नहीं निकाली जा सकेगी।

अंग्रेजों की एक 'भूल' की दिलचस्प कहानी

हुगली नदी के किनारे बसा डायमंड हार्बर

मूल नाम था 'चिंगरीखाली'

निज संवाददाता : दक्षिण 24 परगना जिले में हुगली नदी के तट पर बसा डायमंड हार्बर आज भले ही एक शांत नदी बंदरगाह या सप्ताहांत (वीकेंड) पर घूमने की जगह लगता हो, लेकिन इसका इतिहास बेहद गौरवशाली और रहस्यों से भरा है। यह क्षेत्र अपने भीतर समुद्री डाकुओं के आतंक, नमक के ऐतिहासिक व्यापार और औपनिवेशिक काल के कई उतार-चढ़ावों को समेटे हुए है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि आज जिसे हम डायमंड हार्बर कहते हैं, उसका मूल नाम 'चिंगरीखाली' था। इस नाम के पीछे हुगली नदी में झींगा मछलियों (चिंगरी) की बहुतायत या फिर स्थानीय 'च्वार' जनजाति का प्रभाव माना जाता है। समय के साथ यह नाम बदलकर हाजीपुर हुआ, जो मचलंद पीर की दरगाह और प्लेग के मरीजों के आश्रय स्थल के रूप में जाना गया। बाद में ब्रिटिश शासकों ने इसके भौगोलिक महत्व को देखते हुए इसका नाम 'डायमंड हार्बर' रख दिया। दिलचस्प बात यह है कि 'डायमंड' नाम किसी कीमती रत्न के कारण नहीं, बल्कि यहां होने वाले सफेद नमक के व्यापार की वजह से पड़ा था। सूर्यास्त के समय नदी के किनारे जमा नमक के ढेर हीरे की तरह चमकते थे, जिसे देखकर अंग्रेजों ने इसे यह नाम दिया। 1851 के ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपत्र (गजेटियर) से भी इसके महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह होने के प्रमाण मिलते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह पूरा इलाका मुगल और पुर्तगाली समुद्री लुटेरों (जिन्हें 'हरमद वाहिनी' कहा जाता था) के आतंक से थर्राता था। इन लुटेरों से सुरक्षा और उन्हें खदेड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1868-69 में यहां 'चिंगरीखाली किला' बनवाया, जिसे स्थानीय लोग 'पुराना किला' भी कहते थे।

आज इस किले के अवशेष लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन यह स्थान उस दौर के खूनी संघर्षों की गवाही देता है। डायमंड हार्बर का भारत के आधुनिक विकास में भी बड़ा योगदान रहा है। साल 1851 में देश की पहली टेलीग्राफ लाइन कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच ही बिछाई गई थी। 1857 में इसे उपमंडल मुख्यालय बनाया गया। मशहूर साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी 1864 में यहां डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। 1883 में यहां तक रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, जिसने इसे आधुनिक दुनिया से जोड़ा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, 1930 के नमक सत्याग्रह में यहां के लोगों ने वकील चारुचंद्र भंडारी के नेतृत्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसकी यादें आज भी यहां के 'खादी मंदिर' में सुरक्षित हैं। इस क्षेत्र की प्राचीनता सिर्फ ब्रिटिश या मुगल काल तक सीमित नहीं है। प्रसिद्ध खगोलशास्त्री टॉलेमी के ग्रंथों में वर्णित पालौरा बंदरगाह का संबंध इसी क्षेत्र के अब्दालपुर या पारुल गांव से जोड़ा जाता है। यहां से मिले गुप्त काल के पत्थर के हथियार, टेराकोटा की मूर्तियां और देउलपोता के प्राचीन मंदिर के अवशेष साबित करते हैं कि करीब दो हजार साल पहले भी यह नदी तट एक समृद्ध और विकसित सभ्यता का केंद्र था। भले ही आज वह पुराना किला और नमक की चमक गायब हो चुकी है, लेकिन यहां की हवाओं में इतिहास आज भी जिंदा है।

हल करो हीरो बनो का उत्तर

1.जलाशय, 2.नाइट्रोजन और फास्फोरस,
3.पित्त रस, अग्नाशयी रस

ओबीसी कोटे पर बंगाल सरकार का फैसला आरक्षण नीतियों के लिए एक टर्निंग पॉइंट

संजय सक्सेना

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए हालिया बदलाव ने देश के सबसे संवेदनशील और पुराने विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है आरक्षण, तुष्टिकरण और सामाजिक न्याय का असल चेहरा। राज्य में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने जिस तरह से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) सूची को लेकर कड़ा कदम उठाया है, वह महज एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही वोटबैंक पॉलिटिक्स की बुनियाद पर सीधा प्रहार है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार ने मई 2024 में आए कलकत्ता हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक आदेश को जमीन पर उतारा है, जिसने राज्य में बिना किसी वैज्ञानिक सर्वे और ठोस डेटा के थोक के भाव बांटे गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को असंवैधानिक करार दिया था। नई सरकार का पहला बड़ा राजनीतिक दांव यह रहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट में पिछली ममता बनर्जी सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया। इस एक फैसले ने साफ कर दिया कि नई व्यवस्था अब अदालत के रुख के साथ खड़ी है और 2012 के बाद से सामाजिक न्याय के नाम पर बुने गए उस जाल को पूरी तरह ध्वस्त करने जा रही है, जिसे विपक्षी दल मुस्लिम सब-कोटा का शॉर्टकट बताते रहे हैं।इस पूरे विवाद की जड़ें साल 2010 से जुड़ी हैं, जब राज्य की तत्कालीन वामपंथी सरकार और उसके बाद सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने राज्य के भीतर एक ऐसा सामाजिक समीकरण तैयार करने की कोशिश की, जो चुनावी राजनीति में अजेय किला बन सके। ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान पिछड़ा वर्ग सूची में 140 से ज्यादा नई उप-जातियों को जोड़ा गया था, जिनमें से करीब 80 फीसदी जातियां केवल एक विशेष समुदाय से थीं। आंकड़ों की बाजीगरी ऐसी थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाल में रहने वाले करीब ढाई करोड़ मुसलमानों में से दो करोड़ से अधिक लोगों को कागजों पर रातों-रात ओबीसी घोषित कर दिया गया। अत्यंत पिछड़ों के लिए बनी ओबीसी-ए कैटेगरी में बड़े पैमाने पर मुस्लिम उप-जातियों को जगह मिलने का सीधा नतीजा यह हुआ कि नौकरियों और सरकारी शिक्षा संस्थानों में मिलने वाले कोटे पर एक खास वर्ग का वर्चस्व स्थापित होने लगा। इस पूरी प्रक्रिया ने उन मूल हिंदू पिछड़ी जातियों को हाशिए पर धकेल दिया, जो पीढ़ियों से अपने हक का इंतजार कर रही थीं। माहिष्य, सद्गोप, यादव और कुर्मी जैसी बड़ी पिछड़ी जातियां हों या फिर चुनिया और कलवार जैसे छोटे शिल्पी वर्ग, वे सभी संख्याबल और इस नए मुकाबले में पीछे छूटते चले गए।कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब इस पूरे मामले की परतें खोलीं, तो यह स्पष्ट हो गया कि बिना किसी व्यापक सर्वेक्षण या पिछड़ेपन के वैज्ञानिक मूल्यांकन के पूरी की पूरी आबादी को आरक्षण के दायरे में लाना संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत के इसी फैसले को आधार बनाकर शुभेंदु सरकार ने 2012 के बाद की व्यवस्था को पूरी तरह रद्द कर 2010 की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है, जिसके तहत केवल 66 जातियां ही वैध रूप से ओबीसी कोटे की हकदार मानी गई हैं। इस सूची में कपाली, कुर्मी, नाई (नापित), तांती, धानुक, कसाई, खंडैत, तुरहा, पहाड़िया मुस्लिम, देवांगा और हज्जाम जैसी पारंपरिक जातियों को शामिल किया गया है। साथ ही, अनुसूचित जाति से ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों को भी इस सूची में स्थान मिला है। सरकार का अगला कदम और भी आक्रामक है, जिसके तहत 2011 के बाद से जारी किए गए सभी 1.69 करोड़ जाति प्रमाणपत्रों की व्यापक स्तर पर दोबारा जांच (री-

> इस पूरे विवाद की जड़ें साल 2010 से जुड़ी हैं, जब राज्य की तत्कालीन वामपंथी सरकार और उसके बाद सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने राज्य के भीतर एक ऐसा सामाजिक समीकरण तैयार करने की कोशिश की, जो चुनावी राजनीति में अजेय किला बन सके। ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान पिछड़ा वर्ग सूची में 140 से ज्यादा नई उप-जातियों को जोड़ा गया था, जिनमें से करीब 80 फीसदी जातियां केवल एक विशेष समुदाय से थीं। आंकड़ों की बाजीगरी ऐसी थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाल में रहने वाले करीब ढाई करोड़ मुसलमानों में से दो करोड़ से अधिक लोगों को कागजों पर रातों-रात ओबीसी घोषित कर दिया गया।

वेरिफिकेशन) के आदेश दिए गए हैं। इसमें विशेष रूप से उन प्रमाण पत्रों को खंगाला जाएगा जो द्वारे सरकार जैसे लोक-लुभावन कैंपों के जरिए आनन-फानन में बांटे गए थे।यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई अन्य सूबों में भी मजहब आधारित आरक्षण बनाम संवैधानिक मर्यादा की इस बहस को नए सिरे से जिंदा करता है। कर्नाटक में 1990 के दशक में मुस्लिमों के लिए ओबीसी सूची के तहत जो 4 फीसदी का सब-कोटा तय किया गया था, उसे मार्च 2023 में तत्कालीन सरकार ने असंवैधानिक बताते हुए खत्म कर दिया और मामला अब शीर्ष अदालत के विचाराधीन है। केरल में 1952 से ही लगभग पूरी मुस्लिम आबादी को पिछड़ा वर्ग का लाभ मिल रहा है, जहां हिंदू पिछड़ी जातियां लगातार आरोप लगाती रही हैं कि कोटे का बड़ा हिस्सा एक खास संपन्न वर्ग हड़प लेता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी पूरी आबादी को एकमुश्त आरक्षण देने के प्रयासों को अदालतों ने हमेशा खारिज किया है, जिसके बाद चुनिंदा जातियों को पहचान कर अलग कैटेगरी बनाई गई। इसके विपरीत बिहार जैसे राज्य में मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत केवल पेशेवर और सामाजिक रूप से पिछड़ी मुस्लिम जातियों (जैसे अंसारी और कुरैशी) को ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) में रखा गया है। यह तुलना दिखाती है कि जब भी राज्य सरकारों ने वैज्ञानिक डेटा को दरकिनार कर केवल राजनीतिक लाभ के लिए एकमुश्त समुदायों को पिछड़ेपन का तमगा दिया, वहां कानूनी और सामाजिक टकराव होना तय था।संविधान का अनुच्छेद 16(2) स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव या आरक्षण को प्रतिबंधित करता है, जबकि अनुच्छेद 15(4) केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को ही आरक्षण का वैध आधार मानता है।

1992 के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने यह साफ कर दिया था कि गैर-हिंदू जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए उनका सामाजिक पिछड़ापन एक वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध होना अनिवार्य है। बंगाल में इसी संवैधानिक मर्यादा को ताक पर रखने का आरोप विपक्ष पर लगता रहा है, जहां मुस्लिम वोटबैंक को साधने के लिए जातियों के आंतरिक ढांचे की अनदेखी की गई। राजनीति की इस बिसात पर दोनों पक्षों के नियम एक-दूसरे से पूरी तरह उलट हैं। एक तरफ जहां बहुसंख्यक समाज को एकजुट रखने और सनातनी पहचान के तहत क्षेत्रीय दलों के जातीय कार्ड को बेअसर करने की रणनीति चलती है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के भीतर की उस परत को खोलने का प्रयास हो रहा है जिसे मुख्यधारा की सेक्युलर राजनीति ने हमेशा छिपाकर रखा यानी अशराफ बनाम पसमांदा का भेद। समाज के ऊंचे तबके (सैयद, शेख, पठान) ने हमेशा राजनीतिक और सामाजिक मलाई का आनंद लिया, जबकि जुलाहे, कसाई और बुनकर जैसे गरीब पिछड़े मुस्लिम समाज के हाशिए पर ही रहे। इसके विपरीत, क्षेत्रीय दलों का पूरा वजूद ही इस बात पर टिका है कि बहुसंख्यक समाज अपनी जातियों के छोटे-छोटे ब्लॉकों में बंटा रहे, ताकि जितनी आबादी, उतना हक का नैरेटिव सेट किया जा सके। लेकिन जब बात अल्पसंख्यक समाज की आती है, तो यही दल कभी नहीं चाहते कि वह जातियों या अशराफ-पसमांदा के भेद में बंटे। वहां कोशिश यही होती है कि आंतरिक अंतर्विरोधों के बावजूद वे एक धार्मिक पहचान के तहत एकमुश्त वोटबैंक बने रहें।इस्लामी धर्मशास्त्र के मुताबिक सैद्धांतिक तौर पर इस्लाम में ऊंच-नीच या जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है, और यही तर्क अक्सर आरक्षण के विरोध या समर्थन में धार्मिक मोड़ ले लेता है। लेकिन समाजशास्त्रियों का मानना है कि दक्षिण एशिया और खासकर भारत में, जिन जातियों का धर्मांतरण हुआ, वे अपनी धार्मिक पहचान बदलने के बाद भी अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जातिगत पहचान को नहीं छोड़ पाईं। यही कारण है कि वैचारिक स्तर पर जातियों और फिरकों का विरोध करने वाले धार्मिक गुरु भी आरक्षण के सवाल पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जमीनी स्तर पर मंसूरी या अंसारी की हालत किसी भी रूप में सैयद या शेख जैसी नहीं है। मजहब से बड़ी चुनौती व्यावहारिक पिछड़ापन है। बंगाल का यह नया फैसला देश की भांति-भांति की आरक्षण नीतियों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जो यह तय करेगा कि सामाजिक न्याय का तराजू केवल तुष्टिकरण के पलड़े से हिलेगा या फिर संविधान की कसौटी पर परखा जाएगा।

संपादकीय

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसके राजनीतिक मायने

यह बात जाहिर है कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। इस फैसले में बिहार में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की संवैधानिकता और भारत के चुनाव आयोग की ऐसी एक्सरसाइज़ करने की शक्तियों, दोनों को सही ठहराया गया है। हालांकि, एसआईआर की अहमियत पर कोई सवाल नहीं है : एक साफ़ और अपडेटेड मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की सेहत का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी है। असली चिंता इस बात को लेकर थी कि चुनाव आयोग की देखरेख में एसआईआर को किस तरह से अलग-थलग किया गया : उस राज्य में लगभग 47 लाख लोग, जिनमें से कई सामाजिक-धार्मिक रूप से पिछड़े थे, वोट देने के अधिकार से वंचित थे। खास बात यह है कि इसी आदेश के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि चुनाव आयोग के पास वोटरों की नागरिकता पर फ़ैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार एक ''सक्षम अथॉरिटी'' केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। चुनाव आयोग, जिसने जनता की नज़रों में सत्ताधारी सरकार से खुद को दूर रखने के लिए संघर्ष किया है, उसे इस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार में हटाए गए मतदाताओं के नाम उस मंत्रालय को भेजने के लिए चुनाव आयोग को एक टाइम फ्रेम दिया गया है, जो अब उनकी नागरिकता की स्थिति पर फैसला करेगी। लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल उठता है। अगर नागरिकता तय करना चुनाव आयोग के दायरे से बाहर है, तो उसने इतने सारे लोगों के नाम किस आधार पर हटाए? वोटर्स के अधिकारों का उल्लंघन करके मतदाता सूची की ईमानदारी कैसे बनी रहेगी? बदकिस्मती से, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में बातें साफ नहीं की हैं। उसे करनी चाहिए थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फैसले के असर बहुत बड़े हैं। बंगाल में, लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम पोल रोल से हटा दिए गए : सबसे बड़ी कोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल उनकी वापसी की अर्जी की बहुत धीमी गति से जांच कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही नाम हटाए गए हैं जहां एसआईआर किया गया है। बंगाल में, पेंडिंग एप्लीकेशन (लंबित आवेदन) की स्थिति के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, जिससे इस चुनाव क्षेत्र की चिंता और बढ़ गई है। वोटर लिस्ट से गायब असली नागरिकों के नाम शामिल करना जनता की तुरंत चिंता का विषय है और इसे एक तय समय में सुलझाना होगा। संवैधानिकता का मतलब सिर्फ़ संस्थाओं को मिली शक्तियों को दिखाना नहीं है। इसमें उस संवैधानिक सोच और भावना को भी सुरक्षित करना शामिल है जो सही वोटरों को हटाने के बजाय उन्हें शामिल करने की सोचती है।

पूर्वांचल में सपा के पीडीए को मात देने के लिए बीजेपी का नया दांव

पांच नए जिलाध्यक्षों के चुनाव में रखा क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की गरमा गरमी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में संगठन मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आलाकमान से विचार-विमर्श के बाद पूर्वांचल के पांच जिलों अंबेडकरनगर, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर महानगर और देवरिया के नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इस घोषणा में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को पूरी तरह ध्यान में रखा गया है। दो जिलों में ओबीसी, एक में दलित, एक में वैश्य और एक में क्षत्रिय चेहरे को जिम्मेदारी सौंपकर भाजपा ने सामाजिक संतुलन साधने का स्पष्ट संदेश दिया है। नये जिलाध्यक्षों का बारीकी से आकलन किया जाये तो बीजेपी की 2027 के विधान सभा चुनाव के लिये रणनीति साफ नजर आती है। समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) की काट के लिये बीजेपी पीडीवी (पिछड़ा-दलित-वैश्य) वाला वोट बैंक तैयार कर रही है। अंबेडकरनगर में भाजपा ने दिलीप देव पटेल को नया जिलाध्यक्ष बनाया है। पहले यहां त्रयंबक त्रिपाठी जिलाध्यक्ष थे। दिलीप देव पटेल को संगठन में लंबे अनुभव और ओबीसी समाज में मजबूत पकड़ के चलते जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी इसे सामाजिक संतुलन और संगठन विस्तार के लिहाज से अहम मान रही है। गोरखपुर महानगर में रमेश कुमार गुप्ता को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। देवेश श्रीवास्तव के निधन के बाद यह पद खाली चल रहा था। पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता महानगर संयोजक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। रमेश कुमार गुप्ता को जिम्मेदारी देकर भाजपा ने वैश्य समाज को साधने का स्पष्ट संदेश दिया है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक गढ़ माना जाता है, इसलिए यहां संगठन की कमान मजबूत और अनुभवी चेहरे को सौंपना पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। देवरिया में भाजपा ने काली प्रसाद को नया जिलाध्यक्ष बनाया है। इससे पहले यह जिम्मेदारी भूपेन्द्र सिंह के पास थी। पार्टी ने दलित समाज से आने वाले चेहरे पर भरोसा जताकर सामाजिक समीकरण मजबूत करने की कोशिश की है। संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहने के कारण काली प्रसाद को जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पहचान मिली हुई है। वाराणसी में राम सकल पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जिन्होंने हंसराज विश्वकर्मा की जगह ली है। हंसराज विश्वकर्मा के योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद यह पद खाली हो गया था। राम सकल पटेल लंबे समय से वाराणसी में संगठन के कार्यों से जुड़े रहे हैं और उनकी जमीनी पकड़ मजबूत मानी जाती है। चंदौली में काशीनाथ सिंह को दोबारा जिलाध्यक्ष बनाए रखा गया है। वे संगठन के पुराने और सक्रिय नेताओं में गिने जाते हैं और पार्टी नेतृत्व ने उनके अनुभव और संगठन क्षमता को देखते हुए निरंतरता बनाए रखने का फैसला किया है। नये जिलाध्यक्षों का जातीय आधार पर विश्लेषण किया जाये तो साफ लगता है कि भाजपा के नेतृत्व द्वारा नई टीम समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) गठबंधन की सीधी काट के रूप में तैयार की जा रही है। भाजपा ने जानबूझकर ओबीसी, दलित और वैश्य समाज के चेहरों को मजबूत पदों पर लाने से सपा का पीडीए वोट-बैंक कमजोर कर दिया है। अब ये समुदाय भाजपा को अपनी ओर खींचने वाले अपने चेहरे देख रहे हैं, जिससे सपा की पकड़ ढीली होगी। समाजवादी पार्टी को इस फैसले से तीन स्तर पर गहरा नुकसान हो सकता है। पहला, अंबेडकरनगर जैसे जातीय रूप से संवेदनशील जिले में ओबीसी कुर्मी चेहरा दिलीप देव पटेल आने से सपा का पिछड़ा वोट-बैंक दरक सकता है। यहां पहले ब्राह्मण नेता त्रयंबक त्रिपाठी जिलाध्यक्ष थे, लेकिन अब ओबीसी चेहरा आने से पिछड़े वर्ग का समर्थन भाजपा की ओर मुड़ सकता है। दूसरा, गोरखपुर महानगर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक गढ़ है, में वैश्य समाज के रमेश कुमार गुप्ता को जिम्मेदारी मिलने से सपा का व्यापारी-वैश्य वर्ग भाजपा की ओर झुक सकता है। देवेश श्रीवास्तव के निधन के बाद खाली पद पर वैश्य चेहरा लाना भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। तीसरा, देवरिया में दलित चेहरे काली प्रसाद को लाने से सपा और बसपा का दलित वोट-बैंक कमजोर होगा, क्योंकि भाजपा ने जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पहचान वाले दलित नेता को चुनकर सामाजिक समीकरण मजबूत किया है। भाजपा की यह रणनीति सपा के पीडीए गठबंधन को सीधे तौर पर चुनौती देती है। अब भाजपा ने पिछड़े, दलित और वैश्य समुदायों को अलग-अलग जिलों में नेतृत्व देकर समाजवादी पार्टी को सीमित वोट बैंक वाली पार्टी बना दिया है, जबकि भाजपा अब सामाजिक संतुलन वाला चेहरा दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में अनुभवी और संगठन से जुड़े चेहरों पर भरोसा जताना भी भाजपा की मजबूत रणनीति है। वर्तमान में भाजपा ने उत्तर प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों और महानगरों में से 83 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। मार्च 2025 में 68 जिलों, फरवरी 2026 में 11 जिलों और मई 2026 में अब 5 जिलों के नाम ऐलान हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अब केवल 15 जिलों के जिलाध्यक्ष बनना बाकी हैं। इन 15 बाकी जिलों में अयोध्या, सहारनपुर, अमरोहा, शामली, बागपत, मथुरा जिला, मथुरा महानगर, और पूर्वांचल व ब्रज क्षेत्र के कुछ जिले शामिल हैं। भाजपा की यह तैयारी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए है। पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता बनाए रखने के लिए सामाजिक गठबंधन मजबूत करना जरूरी है। ओबीसी, दलित और वैश्य समाज को अलग-अलग जिलों में नेतृत्व देकर भाजपा ने यह संदेश दे दिया है कि वे सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गौरतलब हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब भाजपा की पिछड़ा-दलित वाली रणनीति का प्रभाव दिखेगा। चुनावी माहौल गरम होने से पहले ही भाजपा ने संगठन मजबूत करके सपा को चुनौती दे दी है। 15 बाकी जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा होने पर यह और साफ होगा कि भाजपा कहां कितनी मजबूत हो रही है। सभी 98 जिलों और महानगरों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पूरी होने के बाद भाजपा का संगठन 2027 चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। भाजपा की यह रणनीति सपा के लिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि भाजपा ने जानबूझकर ऐसे जिलों में चेहरे चुने हैं जहां सपा का पारंपरिक वोट बैंक है। अब सपा को यह साबित करना होगा कि वे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज की असली आवाज हैं और भाजपा की यह नियुक्ति केवल चालाकी है। लेकिन जमीनी स्तर पर ओबीसी, दलित और वैश्य नेताओं को जिम्मेदारी मिलने से सामान्य कार्यकर्ता और वोटर्स पर भाजपा का असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 तक समय है, लेकिन भाजपा ने पहले ही अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। यह रणनीति सपा के पीडीए गठबंधन को तोड़ने और अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। 15 बाकी जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा होने के बाद भाजपा का संगठन पूरी तरह तैयार हो जाएगा और चुनावी मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा।

वृक्षगंधा

गायों के रंभाने की आवाज आने लगी। दूर से धूल की उड़ती गुबार ने गोधूली बेला का शंखनाद कर ही दिया। गायों के गले में बंधे लकड़ी के डिब्बे में लगी घंटी मानो उनके कदमों से जुगलबंदी कर रही हो। ''कृष्णा'' ने गायों को भीतर कोठार में बांधा और चल पड़ी टपरे की ओर...। चारों ओर लकड़ियाँ बिखरी थी। गट्ठा, चिनार, जलाऊ, बत्ता, चिल्फा, बूरा, चूरा, और न जाने क्या-क्या। जिनके यहाँ चिरान (लकड़ी काटने की) की सुविधा थी वे गट्ठड़ (गोले) ले लेते थे। चिरी (चीरा लगाया गया लकड़ी)। एक खास वर्ग की जरूरत होती थी। पतली पट्टियों को 'फारे' की शक्ल में कोई ले जाना चाह रहा था। कोई लकड़ियों के बारिक-बारिक टुकड़े (चिल्फा) को तौलाने आतुर था। कृष्णा को तो पेंसिल छीलने पर निकले छिलके सी पतली लकड़ियों का छिलका चाहिये था। खुले आँगन में लकड़ी के चौकोन पलड़े पर बने तराजू में ''लकड़ी बेचईया'' बड़ा सा बॉट (वजन) रखता और जमीन पर लकड़ियों की विविध किस्मों को पटकता जाता।

''कृष्णा'' काजर सी अंजी आँखें, श्यामवर्ण, कालिया सर्प से केश पर मन एकदम उजला। शाम को चूल्हा जलना है तो लकड़ियों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। कृष्णा का मन तो मन तो जाने कहाँ-कहाँ विचरता था। कभी नदी के पार में महादेव घाट पर वृक्ष में टंगी लाल पोटली को ध्यान से देखा करती। षोडशी कृष्णा को जीवन-मरण की समझ नहीं थीं। वह मन ही मन सोचा करती थी। इस विराने में इन पोटलियों को कोई क्यों नही चुराता? उसे तो बाद में समझ में आया कि कीमत तो जीवित हाड़ माँस की होती है, तन के तंबूरे से निकली इन अस्थियों को सिर्फ और सिर्फ वृक्ष ही यथेष्ट सम्मान दे सकते हैं। आम के पेड़ की शादी भी उसने देखी थी। अम्मा कहती थी कि आम का फल उसकी शादी के बाद ही खाना चाहिये। सब जीवित गुण होने के बाद भी इन वृक्षों को जब काटा जाता होगा तो कितनी पीड़ा होती होगी। वह गायों के रंभाने की आवाज सुन दौड़ पड़ती अपने घर। बूरा सिगड़ी में भर ''चित्तौड़गढ़ के किले'' जैसे जब वह सिगड़ी के नीचे से ऐंठे हुए कागज से आग जलाती तो उसके बाद सिगड़ी की आग, डेगची की भात, छप्पर से निकलती धुएं की लकीरों की जुगलबंदी देखने लायक होती थी। भात की खुशबु से पड़ोस भी गमक जाया करते थे। आज सुबह से मोहल्ले में चहल-पहल थी। 'नुआ बायले' (नई बहु) गाँव आई थी। मंदिर के पास के बरगद जो पूरे गाँव के बाबा स्वरूप थे। उन्हीं की छाँव में नुआ बायले को बिठाया गया। बरगद की सैकड़ों जड़ों ने आज हाथ बनकर आशीष न्यौछावर करने की ठान ली थी। बरगद की पहले पूजा हुई। फिर बाजे गाजे के साथ दुल्हन का गृह प्रवेश। पीपल भी भला कब पीछे रहने वाला था। वह भी साथ हो लिया। सांझ हुई नही कि संध्या दीपक बारने कोई आये इसका इंतजार तो पीपल को भी रहता था। कृष्णा को गाँव के पास के जंगल जाकर गिरी सूखी टहनियाँ बटोरने में ही मन रूचता था। सूखे पत्तों को बुहार कर गट्ठे में बांधना और लाना उसकी और उसकी सखियों का रोज का काम था। उसे यही भला जान पड़ता था। भला कोई जीवित (वृक्ष) हाड़ मांस (शाखों, टहनियों) की चिता जलाता है? ये वृक्ष तो बिना मांगे ही सैकड़ों पत्ते खुशी-खुशी उलीच देते थे। कृष्णा जंगल के आगे भीतर तक जाती जहाँ मधूक (महुआ) के वृक्ष उसके आने के खुशी में गमका करते थे। ''गांव अब शहरिया होने को मचल रहे थे,'' साथ ही संदिग्ध लोगों की उपस्थिति भी उस गांटँव में बढ़ती जा रही थी। बारिश में फुहारों के साथ पत्तों की ता-ता-थैय्या तो, पुरवाई चलने पर पत्तों की और हवा की शहनाई गूँजती थी जंगलो में । इन सबसे कृष्णा का पोर-पोर परिचित था। कौन सा वृक्ष उदास है, किस वृक्ष की अनबन किसके साथ हुई है? किस वृक्ष ने नौनिहाल वल्लरियों को पनाह देने से मना किया है। यह सब हिसाब-किताब कृष्णा को मुँह जुबानी याद था। कृष्णा जब साँझ ढले टोकरियों में सूखे पत्ते लेकर घर आती तो ''पूरा शरीर ही जंगल-जगल लगता।'' वृक्षों की खुशबु से सुवासित वह ''वृक्षगंधा'' ही ज्यादा लगती कृष्णा कम। आज जब कृष्णा जंगल गई तो वृक्षों की संख्या उसे कम लगी। वह बूढ़ा सेमल, वह जवान मधूक, वह नन्हा सागौन... इनकी संख्या में लगातार कमी...। आज तो कृष्ण हतप्रभ थी। कदमों के पदचाप जो संख्या में ज्यादा थे। उनकी आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। कृष्णा का मन आशंका से धड़क उठा साथ ही गाड़ियों की अस्पष्ट आवाज आ रही थी। कृष्णा मन ही मन सोचती थी कि ''मानव शरीर तो वृक्ष के जैसा ही होता है। जमीन से संस्कारों को सोख नस-नस में प्रवाहित विकास-रुधिर से आरक्त होता है।

लड़कियाँ भी वृक्ष जैसी होती हैं। नये जगह में लगाये जाने पर कुछ क्षण तो उदास रहती हैं पर जब वसुधा अपनी छाती पर पनाह देती है तो खुशी से पल्लवित होकर आस-पास को सुवासित कर जाती है।''साँझ घिर आई थी। कृष्णा को जल्द ही घर पहुंचना था। वह अनमने ढंग से पलटी और आधे रास्ते में ही थी कि कुछ लपट सी उठती दिखी। कृष्णा दौड़ी वापस जंगल की ओर। अरे... यह क्या दावानल, लपटें उठती जा रही थी। कृष्णा बदहवास। अभी तो यहां छोटी सी चिंगारी भी नहीं थी। अचानक अपरिचितों के बीच कृष्णा ने खुद को घिरा पाया। अरे ये तुम लोगों ने आग लगाई। ठहरो अभी सबको बुला लाती हूँ। पर कृष्णा के इस उद्घोष के बाद विभित्स हँसी के घेरे ने कृष्णा को घेर लिया। कृष्णा कभी इस वृक्ष को सहलाती कभी उसको। कभी सुलगते वृक्षों को देख रो पड़ती। यह क्या एक हो तो कुछ कर पाये यहाँ तो दावानल फैल चुका था। मानो वृक्षों ने आज साथ जियेंगे साथ मरेंगे वाली कसम बड़ी बेबसी, अवसादित होकर खा ली थी। वृक्षों के पत्ते टहनियों के साथ झुलसकर मँस के लोथड़ों से गिरने लगे थे। पूरे जंगल में वृक्षों के जलने की बास थी। सुबह पूरे जंगल खाक हो चुका है। मानुष गंध भी उस जंगल में घुली थी। मानुष गंध कहाँ वहाँ तो वृक्ष गंधा ही थी। जिसने अपने आपको स्वाहा किया वृक्षों के साथ।

''जंगल-जंगल काया में वृक्ष की बास, वृक्षों की असंख्य रोम छिद्रों सी कृष्णा की त्वचा, छाल उतारने पर निकला रिसाव बस कृष्णा की आँखों से बह रहा था। ''

इन जंगलों के वृक्षों में ही उसका अस्तित्व था। कई दिन बीत गये। लोग कहते हैं कि इस जंगल में एक पेड़ हैं। जिससे मानुष गंध आती है। उसका नाम है-- 'वृक्षगंधा।'वह आज भी इस जंगल में नई कोपलों का इंतजार करती हैं। जंगल की अकेली रखवाली करती है। मृत कृष्णा का अस्तित्व इन जंगले के वृक्षों में ही था। वह वृक्षगंधा बन चुकी थी। चुपचाप निःशब्द।

मार लो मुस्की

गर्लफ्रेंड - सुनो मेरी स्किन बहुत ऑयली-ऑयली हो गई है।
बॉयफ्रेंड - ये लो विम बार, ये स्किन की चिकनाई हटा देगा।
फिर बॉयफ्रेंड की हुई जोरदार कुटाई और हो गया ब्रेकअप।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पत्नी = प्लीज जरा ये ब्रा का हुक लगा दीजिए
पति = मैं 4 किस चार्ज करूंगा।
पत्नी = रहने दो, पडोसी से फ्री में लगवा लेती हूं वो हाथ डाल कर सेट भी कर देगा।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

मोटू- पापा, मुझे बाजा दिला दो।
पापा-नहीं तुम सबको तंग करोगे।
मोटू- नहीं करूंगा पापा, जब सब सो जाएंगे तभी बजाऊंगा।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पतिः- ये कैसा खाना बनाया तुमने,बिलकुल गोबर जैसा?
पत्नीः- हे भगवान, इस आदमी ने हर चीज़ चख रखी है.....

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

परीक्षा में सवाल आया था....
चैलेंज किसे कहते हैं? स्टूडेंट ने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और आखिरी पेज पर लिखा- अगर हिम्मत है तो पास करके दिखाओ?

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

चिंटू से एक आदमी ने पूछा- बेटा, आपके पापा का क्या नाम है?
चिंटू- अंकल, अभी उनका नाम नहीं रखा मैंने, बस प्यार से पापा ही कहता हूं ।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

डॉक्टर : बताइए आपके ये तीन दांत कैसे टूट गए?
मरीज : पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी।
डॉक्टर : अच्छा तो खाने से मना कर देते?
मरीज : डॉक्टर साहब वही तो किया था..

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पप्पू - मेरा भाई दो दिनों तक बैंक नहीं जा सका ।
बंटी - ऐसा क्यों ?
पप्पू - क्योंकि सपनों में उसे लडकी ने चप्पल मारी थी।
बंटी - इसका बैंक न जाने से क्या मतलब?
पप्पू - अरे बैंक में लिखा था... हम आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

टीचर- (खाली जगह भरो) नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली---चली।
गोलू- चूहे खाकर बिल्ली धीरे-धीरे चली।
टीचर- गोलू, मेरे से मजाक ठीक बात नहीं।
गोलू- मैम वो तो मैंने आपका दिल रखने के लिए कह दिया। वरना नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली चलना तो दूर, उठ भी नहीं पाएगी...?

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

दो वकील अदालत में बहस के दौरान व्यक्तिगत कटाक्षों पर उतर आए!!
पहला- तुम से बड़ा गधा मैंने आज तक नहीं देखा!!
दूसरे ने कहा- मैंने भी आज तक तुमसे बड़ा गधा नहीं देखा!!
इस पर जज ने मेज पर हथौड़ा मारते हुए कहा-आर्डर-आर्डर आप दोनों शायद भूल रहें हैं!! कि मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ!!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

लड़का- सर, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं ।
लड़की के पापा- कितना कमा लेते हो महीने में? लड़का- 19,000 हर महीने।
लड़की के पापा- 15,000 तो मैं अपनी बेटी को पॉकेट मनी ही दे देता हूं।
लड़का- वो मिला के ही बोल रहा हूं सर।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

4 लडको को एक बाइक पर सवारी करते ट्रैफिक पुलिस ने रोका पुलिस - ट्रिपल सवारी जुर्म है और तुम चार बैठे हो ?
ये सुनते ही चारो पीछे देखने लगे और एक साथ बोले -''सालो, पाँचवां कहाँ गिर गया? जिससे पार्टी लेनी थी।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

एक बार एक आदमी जंगल से जा रहा था। अचानक उसने शेर देखा फिर सांस रोककर ज़मीन पर लेट गया। ये देख कर शेर आया और उसके कान में बोला! व्रत है बेटा, वरना सारी होशियारी निकाल देता...

जानें अपना राशिफल

मेष
स्नेह भरा समय हो सकता है, कोई बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है जो फायदेमंद होगा, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, मन प्रसन्न रहेगा।

वृषभ
सहायक समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, कोई विदेश में व्यापार करने पर विचार हो सकता है जो लाभदायक होगा, आपसी प्रेम बनाये रखें, मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन
मान–मर्यादा वाला समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी नये व्यक्ति से काम आगे बढ़ सकता है, मन में उत्साह रहेगा।

कर्क
सम्भावना भरा समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, अपने परिवार को प्रसन्न रखें, मन चंचल रहेगा।

सिंह
समृद्ध समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, मित्र पूरा साथ दे सकते हैं, मन में उत्साह रहेगा।

कन्या
व्यापार करने वाला समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है प्रयास करे, मन स्थिर रखें।

तुला
अच्छे अवसर मिलने वाला समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है जो फायदेमंद होगा, अपने परिवार को प्रसन्न रखे, मन शान्त रखें।

वृश्चिक
लक्ष्य प्राप्ति वाला समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है जो लाभदायक होगा, मन प्रसन्न रहेगा।

धनु
अहंकार वाला समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं सोच समझकर ही करे, किसी के बहकावे में आने से झगड़ा भी हो सकता है, अपनी बुद्धिमानी दिखाने की आवश्यकता है, मन वश में रखें।

मकर
सद्भावना रखकर काम करने वाला समय हो सकता है, किसी परिवार के सदस्य से मतभेद भी हो सकता है सावधान रहे, मित्र पूरा साथ दे सकते हैं, मन स्थिर रखें।

कुंभ
सोच–विचार करके काम करने वाला समय हो सकता है, किसी के बहकावे में आने से बनता काम बिगड़ सकता है, अपनी बुद्धिमानी से काम करने की आवश्यकता है, मन में विश्वास रखें।

मीन
आर्थिक मंदी वाला समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी अन्य व्यक्ति से काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करे, मन चंचल रहेगा।

हल करो हीरो बनो

1. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (COD) एक महत्वपूर्ण सूचकांक है जिसका उपयोग इसमें प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए किया जाता है:
(क) वायुमंडलीय वायु (ख) जलाशय
(ग) कृषि योग्य मिट्टी (घ) भूगर्भीय स्तर

2. केरल के बैकवाटर जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ''सुपोषण'' मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की अधिकता के कारण होता है?
(क) पारा और सीसा
(ख) सोडियम और कैल्शियम
(ग) नाइट्रोजन और फास्फोरस
(घ) कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन

3. आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
(क) अग्नाशयी रस, लार
(ख) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेम
(ग) पित्त रस, अग्नाशयी रस
(घ) लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

(उत्तर इसी अंक में)

माथापच्ची–27

	6				3	7		4
	5		6			2		9
	7		4		2			5
				7			2	
		4		6		3		
	9			3				
2			8		9		5	
7		9			6		8	
5		8	7				9	

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक है, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी एवं खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते। उत्तर अगले अंक में

माथापच्ची 26 का हल

3	5	7	1	8	4	2	6	9
8	2	4	9	3	6	5	1	7
1	9	6	7	2	5	8	3	4
2	8	9	6	7	3	4	5	1
6	4	1	8	5	9	7	2	3
5	7	3	4	1	2	9	8	6
7	1	5	3	4	8	6	9	2
9	3	2	5	6	7	1	4	8
4	6	8	2	9	1	3	7	5

स्मार्ट सिटी पर दाग- एनबीसीसी विबग्योर टावर्स के पास खुला फेज-1 कैनाल निवासियों के लिए बना गंभीर स्वास्थ्य संकट

- ठहरे हुए दूषित पानी और मच्छरों के प्रकोप से त्रस्त 100 से अधिक निवासियों ने शुरू की ऑनलाइन याचिका
- एनकेडीए से तत्काल राहत की मांग

सुतपा भट्टाचार्य

आधुनिक बुनियादी ढांचे, विश्वस्तरीय सुविधाओं और सुनियोजित हरित क्षेत्रों के लिए वैश्विक स्तर पर सराहे जाने वाले स्मार्ट सिटी न्यू टाउन की छवि को अपने ही एक आंतरिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी (एनकेडीए) द्वारा शहर के विकास के लिए किए जा रहे तमाम बड़े दावों के बीच, स्थानीय स्तर पर पनप रहा एक गंभीर नागरिक संकट यहां के हजारों निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इस जन-असंतोष का मुख्य केंद्र एनबीसीसी विबग्योर टावर्स आवासीय परिसर के ठीक बगल से गुजरने वाला फेज-1 ओपन कैनाल (खुला नाला) है। मूल रूप से न्यू टाउन की जल निकासी प्रणाली के एक हिस्से के रूप में निर्मित इस कैनाल का उद्देश्य बारिश के पानी की निकासी करना और जलभराव को रोकना था। लेकिन देखरेख के अभाव में यह खुला नाला अब एक बड़े स्वास्थ्य जोखिम में तब्दील हो चुका है। यहां महीनों से जमा सड़ते और ठहरे हुए गंदे पानी के कारण यह क्षेत्र मच्छरों के पनपने का एक स्थाई ठिकाना बन गया है, जिससे क्षेत्र में चौबीसों घंटे असहनीय दुर्गंध और अत्यधिक अस्वच्छता का माहौल बना रहता है। इस संकट की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल एनबीसीसी विबग्योर टावर्स परिसर में ही 500 से अधिक निवासी रहते हैं, और यह फेज-1 कैनाल कई अन्य आवासीय सोसायटियों के बेहद करीब से होकर गुजरता है, जिसके कारण इस खुले नाले से उत्पन्न होने वाला पर्यावरणीय खतरा इस क्षेत्र के हजारों नागरिकों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। स्थानीय पार्कों में खेलने वाले बच्चों से लेकर शाम को टहलने निकलने वाले बुजुर्गों तक, सभी का जीवन दूषित आबोहवा के कारण दूभर हो गया है।

आंदोलन की अगुवाई कर रही स्थानीय निवासी **सुतपा भट्टाचार्य** ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा- सड़ते हुए नाले के ठहरे पानी के किनारे रहना अब पूरी तरह से असहनीय हो चुका है। निवासियों के मुताबिक, इस जहरीली दुर्गंध और मच्छरों के आतंक के कारण उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अत्यंत बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन से समय पर उचित समाधान न मिलने से निराश होकर अब स्थानीय नागरिकों ने इस समस्या के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यक्तिगत शिकायतों से शुरू हुआ यह विरोध अब एक बड़े सामुदायिक आंदोलन का रूप ले चुका है। नागरिकों ने चेंज डाट ओआरजी पर कवर द फेज-1 कैनाल नियर एनबीसीसी विबग्योर प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ नाम से एक ऑनलाइन याचिका शुरू की है, जिसे बेहद कम समय में 100 से अधिक सत्यापित स्थानीय निवासियों का समर्थन मिल चुका है। इस याचिका के माध्यम से सीधे एनकेडीए और पश्चिम बंगाल सरकार से इस खुले कैनाल को तुरंत कंक्रीट स्लैब से ढकने, इसकी नियमित सफाई सुनिश्चित करने और इसके ऊपरी हिस्से को एक सुरक्षित वॉकवे या हरित क्षेत्र में बदलने की मांग की जा रही है। स्थानीय नागरिक संगठनों का कहना है कि न्यू टाउन के ही कई अन्य हिस्सों में कैनाल को बॉक्स-आकार के कंक्रीट स्लैब से ढककर उन्हें खूबसूरत रास्तों और पार्कों में बदलने के सफल उदाहरण मौजूद हैं। ऐसे में एनबीसीसी विबग्योर टावर्स के पास की इस घनी आबादी वाली पट्टी को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? इसे ढकने से न केवल मच्छरों के प्रकोप और बीमारियों के खतरे से मुक्ति मिलेगी, बल्कि यह क्षेत्र स्वच्छ और सुंदर दिखेगा, जो राज्य सरकार के आधुनिक शहरी विकास के दृष्टिकोण के भी अनुकूल होगा। नागरिकों के हस्ताक्षरों और विस्तृत मांग पत्र के साथ इस याचिका की प्रतियां एनकेडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), एनकेडीए के चेयरमैन और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी जा चुकी हैं। प्रभावित निवासियों ने अधिकारियों से इस स्थल का तत्काल संयुक्त निरीक्षण करने, कैनाल को ढकने के काम के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने और इसे आगामी सौंदर्यीकरण योजनाओं में शामिल करने की पुरजोर मांग की है। कोई भी शहर तब तक खुद को पूरी तरह स्मार्ट नहीं कह सकता जब तक उसके टैक्सपेयर नागरिक, खुले और संक्रामक नालों के साए में जीने के लिए मजबूर हों।

यह पूरी तरह से एनकेडीए और संबंधित राज्य अधिकारियों के पाले में है कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझें, नागरिकों को उनके स्वास्थ्य का अधिकार दें और इस गंभीर समस्या का जल्द से जल्द स्थाई निवारण करें। सामुदायिक पहल को अपना समर्थन दें यह जनहित याचिका आम जनता के लिए खुली है। स्थानीय नागरिक इस लिंक (https://c.org/LjwnkLfv8h) पर जाकर इस आंदोलन में अपना ऑनलाइन समर्थन दे सकते हैं।

अत्याधुनिक किया जाएगा बांग्लादेश बॉर्डर

अमित शाह 15 जून को कर सकते हैं दौरा

निज संवाददाता : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों का दौरा कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दौरा बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा, घुसपैठ रोकने और स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस का रिव्यू करने के लिए प्लान किया गया है। हाल ही में, अमित शाह ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान-बांग्लादेश बॉर्डर को टेक्नोलॉजी बेस्ड स्मार्ट बॉर्डर (प्रौद्योगिकी आधारित स्मार्ट सीमा) के तौर पर विकसित किया जाएगा। कहा गया है कि वहां ड्रोन, सेंसर, रडार और मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।इस बीच, अमित शाह ने अगले एक महीने में चार बॉर्डर राज्यों- राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का दौरा करने का भी प्लान बनाया है। कहा जा रहा है कि इस दौरे का मुख्य मकसद बॉर्डर सुरक्षा और घुसपैठ रोकने की स्ट्रैटेजी का रिव्यू करना है। राजनीतिक गलियारों के मुताबिक, बीजेपी 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बॉर्डर, घुसपैठ और आबादी में बदलाव के मुद्दे को और मजबूती से उठाना चाहती है। चर्चा शुरू हो गई है कि केंद्र का ध्यान खासकर उत्तर बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों पर बढ़ रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने के शक में गिरफ्तार लोगों को रखने के लिए हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है। गाइडलाइंस के मुताबिक, संदिग्धों को उन होल्डिंग सेंटर में 30 दिनों तक रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने उन बांग्लादेशियों की पहचान करने पर जोर दिया है जो सीएए या नागरिकता संशोधन कानून में शामिल नहीं हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इन सभी गिरफ्तार अवैध प्रवासियों को सीधे बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। इस संदर्भ में सरकार ने हर जिले के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को निर्देश भेजे हैं, जिसमें कहा गया है, इस राज्य में अवैध रूप से रह रहे सभी बांग्लादेशियों या रोहिंग्याओं को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इन सभी सेंटर का इस्तेमाल इस राज्य की जेलों से रिहा हुए अवैध घुसपैठियों और विदेशी कैदियों को रखने के लिए किया जाएगा। सेंटर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

कोलकाता के सौविक रॉय के पास है 30,000 माचिस के डिब्बों का संग्रह

निज संवाददाता : सोनारपुर के सौविक रॉय के पास 100 नहीं, 1,000 नहीं, 10,000 भी नहीं; बल्कि 30,000 से ज़्यादा माचिस की डिब्बियों का कलेक्शन है, जिसमें कुछ 19वीं सदी की शुरुआत की भी हैं। ज़्यादातर लोग माचिस की डिब्बियों को कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन 62 साल के सौविक ने एक दशक से ज़्यादा समय उन चीज़ों को इकट्ठा करने में बिताया है जिन्हें वह ''दुर्लभ रत्न'' कहते हैं। छोटे-छोटे डिब्बे जिनमें पुराने विज़ुअल्स, विज्ञापनों और डिज़ाइन के ज़रिए कोलकाता के इतिहास के टुकड़े होते हैं।सौविक रॉय एक रिटायर्ड कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं। वे पुरानी यादों की इन चीज़ों को एक बढ़ते हुए आर्काइव के हिस्से के तौर पर संभालकर रखते हैं। एक कलेक्टर (संग्राहक) के तौर पर उनका सफ़र उस दुनिया के पैमाने को समझने से बहुत पहले शुरू हो गया था जिसमें वह आखिरकार जाने वाले थे। उन्होंने याद करते हुए कहा- उस समय, हम सिर्फ़ स्टैम्प और सिक्के इकट्ठा करने के बारे में जानते थे।

हमें नहीं पता था कि इसके अलावा भी इकट्ठा करने की एक पूरी दुनिया है। यह आदत बचपन में 2009 तक एक शांत आकर्षण बनी रही, जब उन्हें कलेक्टरों (संग्राहकों) और दुर्लभ यादगार चीज़ों के एक बड़े नेटवर्क से मिलवाया गया। उस खोज ने धीरे-धीरे उन्हें माचिस की डिब्बियों की अनदेखी दुनिया की ओर खींचाजिसे रॉय छोटे टाइम कैप्सूल के रूप में देखते थे, जिसमें पीढ़ियों से कला, व्यापार, राजनीति और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कहानियां होती थीं। अब उनका घर अतीत की यादगार चीज़ों से भरा है, जो बीते ज़माने की बहुत अच्छे से संभालकर रखी गई हैं। रॉय को माचिस की डिब्बियों का एक ऐतिहासिक आर्काइव बनाने में लगभग 15 साल लगे, जिनमें से ज़्यादातर आज सिर्फ़ अपने लेबल के ज़रिए बची हुई हैं। एक के बाद एक फ़ाइल निकालते हुए, उन्होंने गर्व से अपने विशाल कलेक्शन को दिखाया सिर्फ़ ट्रांसपेरेंट स्लीव (पारदर्शी आस्तीन) के अंदर रखी पुरानी डिब्बियां नहीं, बल्कि इतिहास के ध्यान से डॉक्युमेंटेड टुकड़े। उन्होंने कहा-जिन्हें आज हम माचिस की डिब्बियां कहते हैं, वे असल में कड़ाही हैं। रॉय के आर्काइव में हर माचिस की डिब्बी पर उसकी शुरुआत, बनाने वाले और डिज़ाइन के विकास पर रिसर्च की गई है। उन्होंने बताया-अगर कोई बंगाल के इतिहास के बारे में जल्दी से सीखना चाहता है, तो इन माचिस की डिब्बियों को एक के बाद एक देखना ही काफ़ी होगा।

इतिहास के टुकड़ों की मिलती है झलक

उन्होंने कहा कि भारत में माचिस 1870 के दशक में इंग्लैंड से आयात होकर आई थीं और शुरुआती नमूने लकड़ी के बने होते थे। रॉय ने कहा कि उन्होंने माचिस के लेबल का एक पुराना कलेक्शन खरीदा था जिसमें लगभग 6,000-7,000 लेबल थे। रॉय ने कहा-इसकी हालत बहुत खराब थी। भारत में कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता था। लेकिन कुछ लाख खर्च करने के बाद मैंने इसे खरीदा और फिर छह महीने इसकी स्टडी की। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया असल में कितनी बड़ी है। एक संग्राहक के तौर पर यह उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था।

रॉय ने बार-बार समझाया कि माचिस की डिब्बियां ''छोटी डिस्पोजेबल चीजें'' नहीं हैं, बल्कि वे सोशल डॉक्यूमेंट हैं। उन्होंने कहा-हर माचिस की डिब्बी एक कहानी कहती है... ये छोटे लेबल सोशल बदलाव और इतिहास के टुकड़ों को संभालकर रखते हैं। मेरे कलेक्शन में उस समय ज़्यादातर जापान, स्वीडन और रूस से इंपोर्ट की जाने वाली माचिस की डिब्बियों के नमूने हैं। दक्षिण एशियाई बाज़ार में निर्माता के लिए डिज़ाइन बदले। उदाहरण के लिए, हाथी की इमेजरी आम हो गई, भले ही हाथी जापान जैसे देशों से कल्चरली जुड़े नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में, जापान (स्वीडन के साथ) भारत को माचिस का एक बड़ा एक्सपोर्टर था। भारतीय बाज़ार को पूरा करने और लोकल कॉम्पिटिशन (स्थानीय प्रतियोगिता) को हराने के लिए, जापानी बनाने वाले अक्सर माचिस की डिब्बियों पर भारतीय चेहरे, देवी-देवता और कल्चरल आइकॉन प्रिंट करते थे।

रॉय के कलेक्शन में शुरुआती लकड़ी के ड्रॉअर-स्टाइल और कागज़ की माचिस से लेकर माचिस की डिब्बियां, प्रमोशनल और कसीनो की माचिस, सजावटी लग्ज़री डिज़ाइन, इम्पोर्टेड नमूने और पुराने एक्साइज़ स्टैम्प वाली माचिस शामिल हैं। ज़्यादातर पुराने रिकॉर्ड कहते हैं कि कोलकाता में माचिस नहीं बनती थी, लेकिन बहुत रिसर्च के बाद, रॉय ने पाया कि 1892 और 1893 के आसपास यहां दो कंपनियां थीं। उन्होंने बताया-मेरे पास उन कंपनियों से जुड़े लेबल और डॉक्यूमेंट हैं। मैं इसे साबित कर सकता हूं।उन्होंने कहा-मेरी रिसर्च के मुताबिक, कोलकाता में कभी लगभग 136 माचिस फैक्ट्रियां थीं, हालांकि समय के साथ उनमें से कई धीरे-धीरे गायब हो गईं। रॉय ने कहा-कहा जाता है कि 1960 के दशक में भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय एक फैक्ट्री तबाह हो गई थी, और एक समय में वहां करीब 400 लोग काम करते थे।

आज भी, इनमें से कुछ फैक्ट्रियों के विज्ञापन मिल सकते हैं। रॉय के मुताबिक-आखिरकार, बंगाल ने यह इंडस्ट्री तमिलनाडु के शिवकाशी को दे दी क्योंकि वहां श्रमिक बहुत सस्ती हो गई, प्रिंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत हो गए। बंगाल में शुरुआती पोटेंशियल था, लेकिन वह एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने में फेल रहा।रॉय ने कहा-कहा जाता है कि शिवकाशी के एंटरप्रेन्योर 1920 के दशक में काम सीखने के लिए कोलकाता आए थे, फिर उन्होंने अपने देश में अपनी फैक्ट्री, प्रिंटिंग यूनिट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शुरू किए। उन्होंने आगे कहा-बहुत सस्ते लेबर और मज़बूत बिज़नेस-ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ, शिवकाशी ने धीरे-धीरे मार्केट पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे बंगाल की कभी फलती-फूलती माचिस इंडस्ट्री खत्म हो गई। रॉय ने कहा कि पुरानी माचिस की डिब्बियों पर बने विज़ुअल्स भारत के पॉलिटिकल, सोशल और आर्टिस्टिक बदलाव को दिखाने वाले छोटे कैनवस में बदल गए, जिसमें राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से लेकर अशोक चक्र और वंदे मातरम जैसे नेशनलिस्ट सिंबल या नारे और कोलकाता के ट्रामवे या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या जगहों को दिखाया गया। रॉय को नंबरों की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा- इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास 30,000 या 1 लाख माचिस की डिब्बियां हैं, नंबर ज़रूरी नहीं हैं। क्वालिटी और आर्काइविंग ज़रूरी हैं। अगर इन्हें सरकारी मदद से ठीक से आर्काइव किया जाए, तो हम एक पूरा सामाजिक इतिहास बचा सकते हैं।

बीमारी के कारण पत्नी को अस्पताल में छोड़ दिया

- हाई कोर्ट ने याद दिलाई पति को जिम्मेदारी
- साढ़े चार साल बाद घर लौटी पूनम

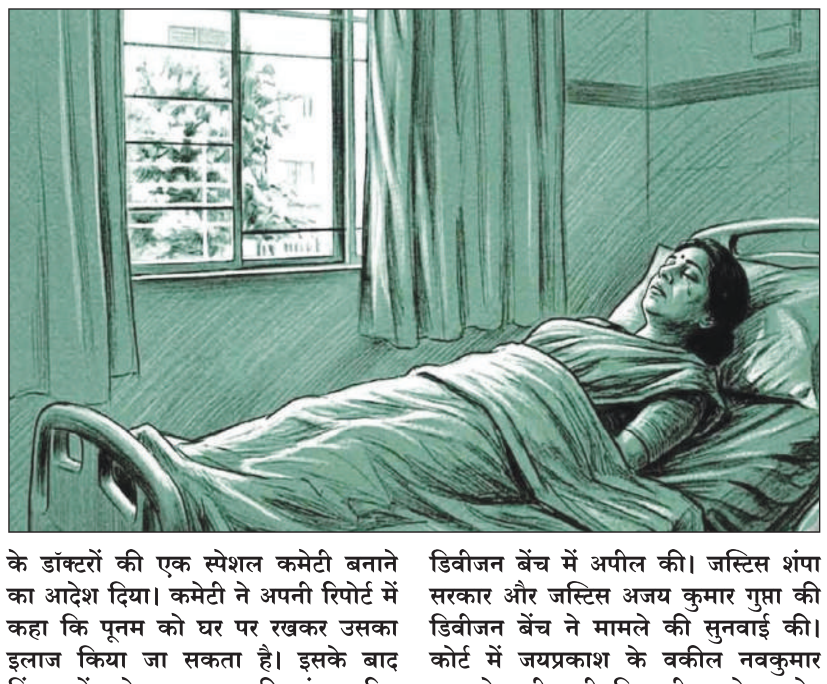

निज संवाददाता : पूनम गुप्ता आखिरकार साढ़े चार साल हॉस्पिटल के बेड पर रहने के बाद घर लौटीं। इतने सालों से बेड पर पड़ी पूनम को उनके पति घर नहीं ले गए थे। उन्होंने हॉस्पिटल का बिल भी नहीं भरा था। आखिरकार, पूनम गुरुवार 21 मई को को हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अमहर्स्ट स्ट्रीट स्थित अपने घर लौट आईं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कोलकाता पुलिस घर पर उन पर नज़र रखेगी कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। पूनम की नियमित देखभाल सरकारी हॉस्पिटल की एक नर्स करेगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी पति अपनी बीमार पत्नी के प्रति अपनी नैतिक, इंसानी और कानूनी ज़िम्मेदारियों से बच नहीं सकता। गौरतलब है कि 15 सितंबर, 2021 को अमहर्स्ट स्ट्रीट पर पूनम का एक्सीडेंट हो गया था। उनके पति जयप्रकाश गुप्ता स्कूटी चला रहे थे, और पूनम उनके पीछे बैठी थीं। वह स्कूटी से गिर गईं और उनके सिर में चोट लग गई। पूनम को पहले कलकत्ता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से उन्हें बाईपास स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। तब से, वह हॉस्पिटल ही पूनम का ठिकाना बन गया। वह बोल या चल नहीं सकती, लेकिन कोर्ट की बनाई मेडिकल कमिटी की रिपोर्ट कहती है कि पूनम इशारों पर जवाब देती है। वह खुद खाना भी खाती है। इस वजह से उसे घर ले जाकर उसका इलाज कराना मुमकिन हो पाया है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अधिकारी भी काफी समय से पूनम के पति जयप्रकाश से बार-बार अपनी पत्नी को घर ले जाने का अनुरोध कर रहे थे। आरोप है कि पेशे से कबाड़ का काम करने वाले जयप्रकाश ने उनकी बात नहीं सुनी। उल्टा, उन्होंने हॉस्पिटल का बिल देना बंद कर दिया। कोर्ट में हॉस्पिटल के अकाउंट के मुताबिक, मरीज के परिवार से अब तक सिर्फ 15 हजार रुपये मिले हैं। और इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख 70 हजार रुपये मिले हैं। हालांकि, 30 सितंबर, 2024 तक के अकाउंट के मुताबिक, पूनम के मेडिकल बिल की रकम 1 करोड़ 9 लाख रुपये है। 9 फरवरी, 2022 को प्राइवेट हॉस्पिटल के अधिकारियों ने जयप्रकाश के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस स्टेशन से मामला नहीं सुलझा, तो उन्होंने 10 मई, 2024 को वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन (डब्ल्यूबीसीईआरसी) में शिकायत दर्ज कराई। कमीशन ने मरीज़ के परिवार को नोटिस भेजकर 24 मई को पेश होने को कहा। आरोप है कि कोई भी पेश नहीं हुआ। इसके बाद कमीशन ने हॉस्पिटल के अधिकारियों से कोर्ट में केस करने को कहा।हाई कोर्ट में दायर केस में जयप्रकाश ने दलील दी कि पूनम वेजिटेटिव स्टेट में है। यानी, अगर वह कोमा में नहीं भी है, तो भी वह नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पा रही है। इसलिए, जयप्रकाश के लिए अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करना मुमकिन नहीं है। पूनम का इलाज सरकारी हॉस्पिटल या घर पर किया जाना चाहिए। जस्टिस कृष्ण राव की बेंच ने मरीज़ की असली हालत का पता लगाने के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की एक स्पेशल कमेटी बनाने का आदेश दिया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पूनम को घर पर रखकर उसका इलाज किया जा सकता है। इसके बाद सिंगल बेंच ने जयप्रकाश की मांग खारिज कर दी और इसी महीने की 8 तारीख को कहा कि पूनम को एक हफ्ते के अंदर घर वापस ले जाया जाए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सकता है। साथ ही जज ने प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल भी माफ कर दिया। जयप्रकाश ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की। जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट में जयप्रकाश के वकील नवकुमार दास ने दलील दी कि मरीज़ को प्राइवेट हॉस्पिटल में छोड़ने की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और उसे घर ले जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। सरकार के पास बीमार या दिव्यांगों के लिए रिहैबिलिटेशन स्कीम होनी चाहिए। सरकार को मरीज़ को होम भेजकर उसके इलाज का इंतज़ाम करना चाहिए। इस मामले में मरीज़ के परिवार की तरफ से वकील सुमंगल शील ने भी दलील दी। हाई कोर्ट ने जयप्रकाश की बात से नाखुशी जताई। डिवीजन बेंच ने कहा कि इस मामले में पति कानूनी तौर पर वैध पत्नी की ज़िम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी दिव्यांग पत्नी को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पति इस तरह अपनी पत्नी की ज़िम्मेदारियों से बच नहीं सकता। इसके अलावा, महिला का एक 17 साल का बच्चा भी है। अगर मां को कहीं और भेजा जाता है, तो वह बच्चा अपनी मां के साथ से दूर हो जाएगा।कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार के पास बुज़ुर्गों, दिव्यांगों और मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए कई तरह के वेलफेयर कानून हैं। लेकिन इस वजह से सभी बीमार लोगों को घर नहीं भेजा जा सकता। फिर, इस फैसले को एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करते हुए, भविष्य में पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन सभी अपने बीमार रिश्तेदारों को छोड़ सकते हैं। इससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा, कोर्ट को यह भी लगा कि सरकार को ऐसी समस्याओं के लिए एक खास पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि, कई मामलों में, परिवार मरीज़ को बोझ समझता है। वे खर्च के डर से मरीज़ को घर नहीं ले जाना चाहते। इसे हल करने के लिए एक सरकारी पॉलिसी की ज़रूरत है।डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए आखिरी फैसले में कहा गया कि फूलबागान पुलिस स्टेशन के ओसी (थाना प्रभारी) पूनम को अस्पताल से अमहर्स्ट स्ट्रीट स्थित उसके घर तक ले जाने का इंतज़ाम करेंगे। उस समय, एक डॉक्टर और एक नर्स मरीज़ के साथ रहेंगे। पुलिस को यह पक्का करना होगा कि पूनम को घर में घुसने में कोई दिक्कत न हो। उसके बाद, उन्हें मरीज़ पर नज़र रखनी होगी। उन्हें देखना होगा कि वह सुरक्षित है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूनम के इलाज के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से हफ़्ते में दो बार एक नर्स भेजी जाएगी। अगर उसकी शारीरिक हालत बिगड़ती है, तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इसके अलावा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी को नियमित तौर पर पूनम के घर जाना होगा और पूछना होगा कि पूनम को किसी कानूनी मदद की ज़रूरत है या नहीं। हालांकि, पूनम के पति ने डिवीजन बेंच के फ़ैसले का स्वागत किया।

उनके वकील ने कहा कि ऐसा नहीं था कि जयप्रकाश अपनी पत्नी को घर नहीं ले जाना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ़ यह दावा किया कि उनके लिए उन्हें इलाज के लिए घर पर रखना मुमकिन नहीं है। यह बात भी कोर्ट को बताई गई। डिवीजन बेंच ने सरकारी अस्पताल में इलाज का आदेश दिया और हफ़्ते में दो बार घर पर एक नर्स भेजने का आदेश दिया। इस फैसले से परिवार को कुछ राहत मिली है। उन्हें फ़ैसला मानने में कोई दिक्कत नहीं है। पूनम गुरुवार 22 मई को दोपहर को फ़ैसला मानते हुए अमहर्स्ट स्ट्रीट पर अपने घर लौट आईं। इस तरह वे साढ़े चार साल की मानसिक परेशानी से अब आज़ाद हो गई हैं।

200 वर्ष की हिंदी पत्रकारिता के सबक

सत्य, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व इसके मूल स्तंभ

हर्षवर्धन पान्डे

भारतवर्ष में पत्रकारिता का अनुभव सदियों पूर्व किया जाता रहा है। किसी न किसी रूप में सनातन काल से कलम साधना की परम्परा सर्वश्रेष्ठ परम्परा रही है। आज हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते है, सुनते हैं, सब कुछ कलम साधना का ही प्रतिफल है। कलम न होती तो शायद संसार में ज्ञान का अस्तित्व ही न होता। ज्ञान न होता तो फिर क्या होता, इस बात का अंदाजा सहज में लगाया जा सकता है। 30 मई 1826 को कलकत्ता से हिन्दी का पहला समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन हुआ था। भारत में जब आधुनिक पत्रकारिता प्रारंभ हुई, तब हमारे पूर्वजों ने इसके लिए दैवीय अधिष्ठान की खोज प्रारंभ कर दी। उनकी वह तलाश तीनों लोक में भ्रमण करने वाले और कल्याणकारी समाचारों का संचार करने वाले देवर्षि नारद पर जाकर पूरी हुई। भारत के प्रथम हिंदी समाचार-पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' के प्रकाशन के लिए संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने देवर्षि नारद जयंती 30 मई, 1826 की तिथि का ही चयन किया। हिंदी पत्रकारिता की आधारशिला रखने वाले पंडित जुगलकिशोर शुक्ल ने उदन्त मार्तण्ड के प्रथम अंक के प्रथम पृष्ठ पर आनंद व्यक्त करते हुए लिखा कि आद्य पत्रकार देवर्षि नारद की जयंती के शुभ अवसर पर यह पत्रिका प्रारंभ होने जा रही है। 30 मई 1826 को हालांकि हिन्दी पत्रकारिता का प्रारंभिक दौर रहा लेकिन पत्रकारिता का अनुभव युगों-युगों से रहा है। देवर्षि नारद इस पत्रकारिता जगत के आदि पुरुष माने गये हैं। इन्हीं के अथक परिश्रम के प्रभाव से सांस्कृतिक पत्रकारिता का उदय हुआ। ऐसा नहीं है कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने ही पत्रकारिता के अधिष्ठात्रा देवता के रूप में देवर्षि नारद को मान्यता दी, अपितु अन्य प्रारम्भिक व्यक्तियों ने भी उनको ही संचार का प्रेरणास्रोत माना। देवर्षि नारद पत्रकारिता के पितामह हैं। पत्रकारिता उन्हीं से शुरू होती है। 'रुद्रप्रयागे तन्वगिंग सर्वतीर्थोत्तमे शुभे।' श्री केदार महात्म्य के 63वें अध्याय के अनुसार देवाधिदेव महादेव की स्तुति कर देवर्षि नारद ने पत्रकारिता के पूर्ण रहस्य लोक कल्याण हेतु प्राप्त किये। उन्होंने शिव सहस्रनाम की रचना कर त्रिलोक्य दीपक संगीत रूपी पत्रकारिता संसार के सम्मुख रखी। तभी यह ज्ञान सामने आया कि ''नाद से वर्ण, वर्ण से पद, पद से वाक्य और वाक्य वचन से ही समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है इसलिए संसार नादात्मक है अर्थात शब्द ही ब्रह्मा है। यदि शब्द ही ब्रह्म है तो शृष्टि की रचना के साथ ही पत्रकारिता का जन्म हुआ है। शिव से पुरुषाकृत छह राग उत्पन्न हुए, जो राग पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं में 'त्रिलोक दीपक' एक है। इसके अलावा देह सोधन ज्ञान से देह में अधिष्ठित सार्व भौतिक ज्ञान व समस्त भूतों को जानने की कला का ज्ञान, संगीत कला के तत्व से नाद का विधान, संगीत की समस्त विद्याओं का ज्ञान, स्वरों के भेद का पूर्ण ज्ञान, संगीत में स्वर शब्द के मूल में षांडवों का वर्णन गायन क्रिया तथा अलंकारों के भेद स्थायी, आरोही, अवरोही, संचारी का ज्ञान, सप्तस्वर षडजी, ऋषिजी, गांधारी, मध्यमा, पंचमा, छठी, धैवती, नौसादी का ज्ञान स्वरों के भेद और तालों की संज्ञा का ज्ञान उपहन्तु, गल, विशारद, अर्थभोग के अलावा स्वरों के भेद की बहत्तर कलाओं का ज्ञान, जिनमें प्रमुख रूप से गमन कला, रसायन कला, अंगलेखन कला, हास्य लेखन कला प्रमुख हैं। 'भोजन योजनचैव हास्यलिखनमेव च',पढ़ना, वचन, परिचर्चा, देवविद्या कला, संग्राम, तांत्रिक, मांत्रिक, व्यवहार कला आदि के उद्गमकर्ता देवर्षि नारद रहे हैं। देवर्षि नारद जी को सृष्टि का प्रथम पत्रकार माना जाता है वहीं नारद मुनि हिन्दू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों में एक हैं। भगवान विष्णु के प्रति इनकी अचल निष्ठा है और लोक कल्याण के लिए सर्वत्र विचरण करना इनका प्रमुख धर्म है। पत्रकारिता के साथ साथ भक्ति तथा संकीर्तन के ये आदि आचार्य हैं। इनकी वीणा ही इनका संचार पत्र था जिसे 'महती' के नाम से पुकारा जाता है। पत्रकारिता के इस महत्व को गीता में समझाते हुए योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने देवर्षियों में नारद को अपनी विभूति बताया हैं। नारद के भक्ति सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन सूत्रों में पत्रकारिता के आधारभूत सिद्धांत शामिल हैं। ये सूत्र पत्रकारिता को दिशा देने वाले हैं। देवर्षि नारद के संपूर्ण संचार का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि वह लोककल्याण के लिए संवाद का सृजन करते थे। समय के बदलते स्वरूप में सम्राट अशोक के समय में नगर के दीवारों में लेख व समस्याएं लिखकर पत्रकारों ने पत्रकारिता की। मुगलों के समय में प्रत्येक जिले में वाकयानवीश के रूप में पत्रकार नियुक्त रहते थे।

भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सन् 1550 ई0 में पहला छापाखाना लगाया गया, जहां ईसाई धर्म की पुस्तकें मलयालम भाषा में छपी।1662 ई. में भीमाजी पारख नामक व्यक्ति ने दूसरा छापाखाना लगाया और1664 ई. में पहला अंग्रेजी छापाखाना लगा व 1772 ई. में भारत में पहला सरकारी छापाखाना लगा। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयत्न ईस्ट इंडिया कंम्पनी के अधिकारी विलियम बोल्टस ने किया। 1780 में जेम्स आगस्टन हिक्की ने 'बंगाल गजट' जिसे कोलकाता जर्नल एडवाईजर भी कहा गया, नामक पत्रिका का प्रकाशन कर नींव रखी। 1782 में सरकार विरोधी गतिविधियों के चलते यह अखबार बंद हो गया। 1785 में 'बंगाल जर्नल' अखबार के सम्पादक को ब्रिटिश सरकार की नीतियां उजागर करने पर भारत छोड़ना पड़ा। 1790 तक पत्रकारिता एंग्लो इंडियन समाचार पत्र तक सीमित रही। पत्र अंग्रेजी में थे। प्रेस सम्बन्धी कोई कानून नहीं था। 1822 में फारसी भाषा में पत्र 'मिराद-उल' अखबार राजा राममोहन राय ने निकाला। राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया। समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किये और अपने पत्रों के जरिए जनता में जागरूकता पैदा की। हिन्दी पत्रकारिता की यात्रा लगभग 200 वर्ष पुरानी है। 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित उदन्त मार्तण्ड को हिन्दी पत्रकारिता का प्रथम प्रकाशन माना जाता है। 'उदन्त मार्तण्ड' का शाब्दिक अर्थ है 'उगता हुआ सूर्य'। यह एक

साप्ताहिक समाचार पत्र था जो प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होता था। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता के गौरवशाली परंपरा को सहेजने का अवसर है। इस तरह चलते-चलते 30 मई 1826 को हिन्दी पत्रकारिता का उदय हुआ। पं. युगल किशोर शुक्ल इस समाचार पत्र के सम्पादक थे, जो सम्भवतः हिन्दी पत्रकारिता के पहले सम्पादक थे हालांकि आर्थिक कठिनाइयों के चलते 11 दिसम्बर 1827 को यह समाचार पत्र बंद हो गया था लेकिन हिन्दी पत्रकारिता ने इस दौर से धीरे-धीरे जो तेजी पकड़ी वह अब तक अनवरत जारी है। आर्थिक कठिनाइयों और बंगाल में हिंदी का प्रचलन नहीं होने के कारण लगभग डेढ़ वर्ष में ही यह बंद हो गया। लेकिन इसने हिंदी पत्रकारिता के सूर्य को उदित कर दिया था जो आज भी दैदीप्यमान है। हिंदी पत्रकारिता ने लोगों को जागरूक करने, समाज को सही दिशा देने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी की लड़ाई में हिंदी समाचार पत्रों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने और देशभक्ति की भावना जगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1826 से लेकर 1867 तक का समय हिन्दी पत्रकारिता का प्रारम्भिक युग माना गया है। इसी चरण में 1845 को बनारस साप्ताहिक पत्र निकला। इसी दौर में 10 मई 1845 को अंग्रेजी पत्र 'हिन्दू हेरल्ड' को हिन्दी में 'बंग दूत' के नाम से निकाला गया जिसके सम्पादक नील रत्न हालदार थे। फिर 1846 में 'इंडियन सन' के अलावा बांग्ला, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू आदि अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ। 1867 से 1900 तक का समय भारतेन्दु युग के नाम से पत्रकारिता जगत में प्रसिद्ध रहा। इस युग में 15 अगस्त 1867 को 'कवि वचन सुधा' नामक मैगजीन निकाल कर भारतेन्दु ने पत्रकारिता जगत में नई क्रान्ति को जन्म दिया। हरीश्चन्द्र मैगजीन सहित इस युग में लगभग 300 से अधिक समाचार पत्र समूचे राष्ट्र से निकले। कविवचन सुधा (1867), अल्मोड़ा अखबार (1871), हिंदी दीप्ति प्रकाश (1872), बिहार बंधु (1872), सदादर्श (1874), हिंदी प्रदीप (1877), भारत मिश्र (1878), सारसुधानिधि (1879), उचितवक्ता (1880), ब्राह्मण (1883) इस काल के प्रमुख पत्र हैं। सन 1900 से 1920 तक का समय इस क्षेत्र में द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग में प्रखर पत्रकार रहे। 'सरस्वती मैगजीन' व 'भारत मित्र' इस दौर की चर्चित पत्रिका रही। इस युग में सैकड़ों पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। हिंदी पत्रकारिता के विकासक्रम में कुछ पत्रकार प्रकाश स्तंभ बने जिन्होंने अपने समय में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अनेक समाचार पत्र ने आजादी की अलख को जगाए रखने का प्रयास किया। हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध, उन्नत व बहुमुखी बनाने में भारतेन्दु का योगदान अद्वितीय है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का अंकुरण किया। कविवचन सुधा (1867), अल्मोड़ा अखबार (1871), हिंदी दीप्ति प्रकाश (1872), बिहार बंधु (1872), सदादर्श (1874), हिंदी प्रदीप (1877), भारत मिश्र (1878), सारसुधानिधि (1879),उचितवक्ता (1880), ब्राह्मण (1883) इस काल के प्रमुख पत्र हैं।1920 से 1947 तक गांधी युग के समय में समाचार पत्रों की बाढ़ सी आ गयी। महात्मा गांधी ने कहा था कि पत्रकारिता का पहले उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना, उनमें वांछनीय उद्देश्यों को जागृत करना और सार्वजनिक दोषों को निर्भीकतापूर्वक प्रकट करना है अर्थात समाज को बदलना ही पत्रकारिता का मुख्य दायित्व है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता अपने दायित्वबोध से भावी पीढ़ी के लिए आदर्श स्थापित कर पायेगी। अंग्रेजों की दासता में बर्बादी और अपमान झेलते भारत की दुर्दशा के कारणों की पहचान भारतेंदु काल से ही शुरू हो गई थी, इसे राजनीतिक और सांस्कृतिक सरोकारों से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गहराई से जोड़ दिया। इसी दरम्यान भूमिगत पत्रकारिता भी अपने कौशल से इंकलाब को रोशन कर रही थी किंतु महात्मा गांधी के सत्याग्रही नेतृत्व ने कुछ भी भूमिगत नहीं रहने दिया और पत्रकारिता ने भी इस साहस को अपने प्राणतत्व के रूप में मंजूर किया। इसका ज्वलंत उदाहरण बना गणेश शंकर विद्यार्थी का 'प्रताप' अखबार। यह कानपुर से छपता था। इसी परंपरा में वाराणसी से बाबूराव विष्णु पराडक़र ने 'दैनिक आज' निकाला और आगरा से पालीवाल जी ने 'सैनिक'। अब डंके की चोट पर हुक्मरानों की बर्बरता, सामाजिक कुरीतियों और रूढिय़ों के खिलाफ संपादकीय और समाचार प्रकाशित होने लगे। प्रेमचंद, निराला, बनारसीदास चतुर्वेदी, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, शिवपूजन सहाय आदि की सशक्त उपस्थिति 'जागरण', 'हंस', 'माधुरी', 'अभ्युदय', 'मतवाला', 'विशाल भारत' आदि के रूप में दर्ज होने लगी। सच कहें तो यही वह दौर था जब पत्रकारिता के जम्हूरियत में चौथे खम्भे का दर्जा प्राप्त करने की बुनियाद पड़ गई थी। इस युग में राष्ट्र रत्न शिव प्रकाश गुप्त के नेतृत्व में 'दैनिक आज' का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसका नाम स्वयं महात्मा गांधी ने रखा। गांधी जी ने 'सत्याग्रह', 'यंग इंडिया', 'नवजीवन' आदि पत्रों का प्रकाशन कर देश को जगाने व मानसिक तौर पर तैयार करने का काम किया। सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से उन्होंने 'हरिजन', 'हरिजन सेवक' और 'हरिजन बंधु' नाम के भी पत्र निकाले।

> ***हिंदी साहित्य से जुड़े व्यक्तियों का हिंदी पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसे तत्कालीन अख़बारों ने शिद्दत से निभाया। उस समय पत्रकारिता एक मिशन थी लेकिन समय के साथ- साथ मिशन ''प्रोफेशन'' में तब्दील हो गया। जैसे-जैसे सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन आता गया, पत्रकारिता भी उससे प्रभावित होती गयी। अखबार अब सिर्फ खबरों को जानने का साधन नहीं रहे बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण खबरें बनाने भी लगे क्योंकि चौबीस घंटे चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलाए जाने लगे। व्यवसायिकता और टी.आर.पी.की अंधी दौड़ ने पत्रकारिता के मूल्यों को बदल के रख दिया। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार भारत में डिजिटल मीडिया बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा कंटेंट खासकर हिन्दी का बड़ा योगदान है। इधर हिन्दी ने अंग्रेजी मीडिया के दबदबे को काफी हद तक चुनौती दी है क्योंकि इस दौर में हिंदी बाज़ार की भाषा बन चुकी है।***

स्वाधीनता के बाद से पत्रकारिता ने जो तेजी पकड़ी उसका कोई जवाब नहीं है। दीगर है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पं.गणेश शंकर विद्यार्थी,बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अंबिकादत्त व्यास और बालमुकुंद गुप्त, राजेंद्र माथुर ,राहुल बारपुते और प्रभाष जोशी सरीखे अनेक प्रखर सम्पादकों ने हिंदी पत्रकारिता को सशक्त किया है। पत्रकारिता के विकास क्रम में इन सरीखे कई पत्रकार हिंदी के प्रकाश स्तंभ बने जिन्होंने अपने समय में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जनसरोकारों की अलख को जगाए रखने का प्रयास किया। आज धार्मिक, राजनीतिक, फिल्मी, स्वास्थ्य सहित अनेक विषयों पर पत्र-पत्रिकाओं को आये दिन प्रकाशन हो रहा है। मिशन रूपी पत्रकारिता आज व्यवसायिकता में भी तब्दील होते जा रही है। पत्रकारिता पर राजनीति का हावी होना भी अच्छा संकेत नहीं है लेकिन पत्रकारिता का सौभाग्य यह है कि 'कलम की ताकत' आज भी सर्वश्रेष्ठ है। आजादी की जंग से लेकर भारत में लोकतंत्र के निर्माण तक हिंदी पत्रकारिता का योगदान अतुलनीय रहा।30 मई, 1826 ई. के बाद से सांस्कृतिक जागरण, राजनीतिक चेतना, साहित्यिक सरोकार और दमन का प्रतिकार इन चार पहियों के रथ पर सवार होकर लगातार आगे बढ़ी है। हिंदी साहित्य से जुड़े व्यक्तियों का हिंदी पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसे तत्कालीन अख़बारों ने शिद्दत से निभाया। उस समय पत्रकारिता एक मिशन थी लेकिन समय के साथ- साथ मिशन ''प्रोफेशन'' में तब्दील हो गया।

जैसे-जैसे सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन आता गया, पत्रकारिता भी उससे प्रभावित होती गयी। अखबार अब सिर्फ खबरों को जानने का साधन नहीं रहे बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण खबरें बनाने भी लगे क्योंकि चौबीस घंटे चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलाए जाने लगे। व्यवसायिकता और टी.आर.पी.की अंधी दौड़ ने पत्रकारिता के मूल्यों को बदल के रख दिया। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार भारत में डिजिटल मीडिया बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा कंटेंट खासकर हिन्दी का बड़ा योगदान है। इधर हिन्दी ने अंग्रेजी मीडिया के दबदबे को काफी हद तक चुनौती दी है क्योंकि इस दौर में हिंदी बाज़ार की भाषा बन चुकी है। मूर्धन्य संपादक शिवपूजन सहाय ने एक बार कहा था कि भारत की साधारण जनता तक पहुंचने के लिए दैनिक पत्र ही सर्वोत्तम साधन हैं। देश-देशांतर के समाचारों के साथ भाषा और साहित्य का संदेश भी दैनिक पत्रों द्वारा आसानी से जनता तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते आये हैं।

आज मीडिया कन्वर्जेंस के इस दौर में भले ही प्रसार से लेकर विज्ञापन और राजस्व सरीखी तमाम चुनौतियां खड़ी हैं लेकिन एक बात साफ़ है समाचार पत्रों के प्रति जनता का भरोसा और विश्वसनीयता बरकरार है। तमाम चुनौतियों के बाद भी हिंदी पत्रकारिता निरंतर आगे बढ़ रही है। 200 वर्ष की हिंदी पत्रकारिता की यात्रा हमें सिखाती है कि सत्य, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व ही इसके मूल स्तंभ हैं। भविष्य में तकनीक, जनसरोकार और जवाबदेही की राह पर चलकर ही हिन्दी पत्रकारिता टिकेगी।

विदेशी मीडिया को मिला भारत पर उंगली उठाने का आसान मौका

अजय कुमार

नॉर्वे सिर्फ अपने ठंडे, बर्फीले समुद्र तटों और मछलियों के निर्यात के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि उसकी एक सालाना वैश्विक आदत भी है पूरी दुनिया की क्लास लेना और यह बताना कि तुम सब लोकतंत्र का ककहरा गलत पढ़ रहे हो। इसे कूटनीतिक हलकों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहा जाता है। इस फेहरिस्त में भारत की रैंकिंग का हाल बहुत अच्छा नहीं रहा है और हम 157वें पायदान पर खड़े दिखते हैं। लेकिन इस बार ओस्लो से जो कहानी आई, वह सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं थी, बल्कि उसमें एक सनकी कूटनीति, सोशल मीडिया का उथलापन और हमारी अपनी पुरानी गौरववादी ग्रंथियों का एक अजीब घालमेल था। पूरी कहानी की मुख्य किरदार बनीं सुनहरे बालों वाली पत्रकार हेल लिंग, जो वहां के एक ऐसे अखबार से जुड़ी हैं जिसे खुद नॉर्वे के बहुसंख्यक लोगों ने शायद ही कभी पढ़ा हो। वह एक ऐसे देश के मुखिया के सामने तीखे सुर में चिल्ला रही थीं, जहां के भूगोल और राजनीति का उन्हें बहुत सतही अंदाजा था।यह पूरा वाकया दोनों प्रधानमंत्रियों की एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हुआ, जिसे कूटनीति की भाषा में फोटो-ऑप कहा जाता है। दुनिया का हर मंझा हुआ पत्रकार जानता है कि यह जगह गंभीर या खोजी सवाल-जवाब के लिए नहीं, बल्कि आपसी समझौतों पर मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने का एक कूटनीतिक थिएटर होती है। मगर हेल लिंग ने इसे अपने लिए कंटेंट बनाने का सही मौका समझा। जब प्रधानमंत्री कमरे से बाहर जाने लगे, तो उन्होंने चिल्लाते हुए प्रेस की आजादी पर तंज कसा और फिर इतने पर ही नहीं थमीं, बल्कि लिफ्ट तक उनका पीछा किया। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करते हुए कई पोस्ट दाग दिए। सामान्य स्थिति में इसे एक उतावली पत्रकार की बचकानी हरकत मानकर टाला जा सकता था, लेकिन हमारे राजनयिक तंत्र ने यहीं पर बड़ी नासमझी कर दी। भारतीय दूतावास ने अति-आत्मविश्वास में आकर उसी शाम हेल लिंग को एक औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग में आमंत्रित कर लिया। लगा कि भारतीय पक्ष बड़ी दिलदारी और लोकतांत्रिक बड़प्पन दिखाना चाहता है, लेकिन वह कदम कूटनीतिक रूप से आत्मघाती साबित हुआ। जब उस ब्रीफिंग में पत्रकार ने तीखे लहजे में पूछा कि दुनिया भारत पर भरोसा क्यों करे, तो हमारे विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने सीधे और तार्किक जवाब देने के बजाय एक लंबा-चौड़ा ऐतिहासिक व्याख्यान शुरू कर दिया। जवाबों में अचानक सरस्वती नदी की प्राचीन सभ्यता, शतरंज के खेल का आविष्कार, योग की महत्ता और कोरोना काल की वैक्सीन डिप्लोमेसी का जिक्र होने लगा। इसे कूटनीति नहीं कहते; यह तो ऐसा लगा जैसे कोई विदेश मंत्रालय किसी अंतरराष्ट्रीय प्रेस वार्ता को प्राचीन भारत के इतिहास पर स्कूल का कोई प्रोजेक्ट समझने की भूल कर बैठा हो। जब आप तीखे कूटनीतिक सवालों के जवाब में प्राचीन गौरवासन का सहारा लेते हैं, तो आप एक ही समय में कमजोर और बड़बोले, दोनों नजर आने लगते हैं। राजनयिकों के दिमाग में यह साधारण सी बात नहीं आई कि इस तीखेपन का रुख मोड़ा जा सकता था। उस

प्रेस फ्रीडम के संदर्भ में नार्वे की घटना

> **असली समस्या प्रधानमंत्री का उस शोर में जवाब न देना नहीं था, असली समस्या भारत के भीतर पिछले 11 सालों से बनी वह व्यवस्था है जहां कोई औपचारिक, बिना स्क्रिप्ट वाली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती जहां मीडिया खुलकर कोई भी सवाल पूछ सके। हमारे पास सैकड़ों टीवी चैनल जरूर हैं, लेकिन उनके पास पूछने के लिए सीधे सवाल नहीं हैं। इसी चुप्पी और कूटनीतिक तंत्र की बड़बोली घबराहट ने विदेशी मीडिया को भारत पर उंगली उठाने का एक आसान मौका दे दिया।**

पत्रकार से पूछा जाना चाहिए था कि अगर भारत भरोसे के लायक नहीं है, तो आपकी अपनी नॉर्वेजियन सरकार ठीक उसी समय हमारे साथ अरबों डॉलर की व्यापारिक डील क्यों साइन कर रही थी? वहां के राजा ने भारतीय प्रधानमंत्री से हाथ क्यों मिलाया और वहां की संसद ने इन समझौतों पर सहमति क्यों जताई? मगर हुआ यह कि माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और पत्रकार को एक बार गुस्से में कमरे से बाहर भी संक्षिप्त कूटनीतिक जवाब की जगह इतिहास का पाठ पढ़ाया गया। इस कूटनीतिक रायते को और फैलाने का काम हमारे घरेलू इंटरनेट और सोशल मीडिया ब्रिगेड ने किया। सोशल मीडिया पर यूजर्स दो धड़ों में बंट गए। एक वर्ग ने हेल लिंग के पुराने चीनी झुकाव वाले लेखों और अमेरिकी प्रशासन की आलोचनाओं को ढूंढ निकाला और उन्हें विदेशी एजेंट या चीनी प्रॉक्सी करार दिया। उनकी चुप्पी और अचानक एक्स पर आए ब्लू टिक को एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश के सबूत के तौर पर पेश किया गया। हालांकि पत्रकार ने बाद में सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ अपनी एक स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारने के लिए पैसे देकर वह सब्सक्रिप्शन लिया था और वह इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं। इंटरनेट ने इस सफाई को दरकिनार कर दिया, लेकिन इस पूरी ट्रोलिंग का उलटा असर यह हुआ कि सोमवार तक महज 800 फॉलोअर्स वाली एक साधारण कमेंटेटर अचानक 17 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेस फ्रीडम का नया चेहरा बन गई।भारतीय राजनीति ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने में देर नहीं लगाई। विपक्ष के शीर्ष नेताओं ने इस घटना के वीडियो को साझा करते हुए सरकार की छवि पर सवाल उठाए और पूछा कि जब प्रधानमंत्री दुनिया के सामने सवालों से बचते हैं, तो देश की साख का क्या होता है। हालांकि, विपक्ष का यह तर्क भी थोड़ा कमजोर था, क्योंकि दुनिया के किसी भी परिपक्व लोकतंत्र में कोई प्रधानमंत्री किसी विदेशी नेता के साथ जॉइंट फोटो सेशन के शोर में इस तरह चिल्लाकर पूछे गए असंगत सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होता। असली समस्या प्रधानमंत्री का उस शोर में जवाब न देना नहीं था; असली समस्या भारत के भीतर पिछले 11 सालों से बनी वह व्यवस्था है जहां कोई औपचारिक, बिना स्क्रिप्ट वाली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती जहां मीडिया खुलकर कोई भी सवाल पूछ सके। हमारे पास सैकड़ों टीवी चैनल जरूर हैं, लेकिन उनके पास पूछने के लिए सीधे सवाल नहीं हैं। इसी चुप्पी और कूटनीतिक तंत्र की बड़बोली घबराहट ने विदेशी मीडिया को भारत पर उंगली उठाने का एक आसान मौका दे दिया। तमाशा यहीं खत्म नहीं हुआ। इस पूरे विवाद के बाद नॉर्वे के एक प्रमुख अखबार ने नस्लवाद की सारी हदें पार करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री का एक बेहद आपत्तिजनक कार्टून छाप दिया, जिसमें भारत को फिर से सांप-सपेरों के पुराने औपनिवेशिक चश्मे से देखने की कुंठा साफ नजर आई। खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का मसीहा बताने वाले देश के मीडिया एथिक्स वहां आकर दम तोड़ गए। जो देश तकनीक, डिजिटल यूपीआई क्रांति और जीवन रक्षक दवाओं के लिए भारत पर निर्भर है, उसका मीडिया आज भी 140 करोड़ की आबादी वाले देश को उसी पुरानी सामंती सोच से आंक रहा है। लब्बोलुआब यह है कि न तो फोटो-ऑप के दौरान उस विदेशी पत्रकार का वह ड्रामा पत्रकारिता थी, न हमारी सभ्यता वाला वह लंबा व्याख्यान कूटनीति था, और न ही इंटरनेट की वह अंधी ट्रोलिंग देश का सम्मान बचा रही थी। इस पूरे प्रकरण में सबने सिर्फ अपने हिस्से की राजनीतिक और डिजिटल रोटियां सेंकीं, और जो सच कड़वे सवाल के रूप में लिफ्ट के बंद दरवाजों के पीछे छूट गया था, वह आज भी वहीं खड़ा है।

केरलम की जीत ने बढ़ाई यूपी चुनाव में कांग्रेस-मुस्लिम लीग गठबंधन की संभावना

इतिहास यह भी बताता है कि जब-जब मुस्लिम मतदाता बंटे हैं, तब-तब भाजपा ने उसका लाभ उठाया है। ऐसा लगता है कि केरलम में मुस्लिम लीग की बढ़ी ताकत, यूपी में ओवैसी का विस्तार, कांग्रेस-सपा में दरार और बसपा से नये गठबंधन की संभावना। ये सभी मुद्दे मिलकर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देश का सबसे जटिल और रोचक चुनावी मैदान बनाने वाले हैं। यूपी की 403 सीटों पर जो भी समीकरण बनेगा, वह न केवल प्रदेश की, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम वोट का बिखराव किसको फायदा पहुंचाएगा और किसका सियासी किला ढहाएगा।

निज संवाददाता : केरलमम में कांग्रेस व मुस्लिम लीग की जीत ने बढ़ाई 2027 के यूपी चुनाव में गठबंधन की संभावना केरलम में कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बन चुकी है। इस गठबंधन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुमत के लिए कांग्रेस को उसके सहयोग पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ेगा। दक्षिण भारत के एक राज्य की इस जीत ने जहां कांग्रेस के लिए राहत की सांस दी है, वहीं मुस्लिम लीग के हौसले इतने बुलंद हो गये हैं कि उसकी नजर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी टिक गई है। केरलम में सरकार बनने के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरलम से बाहर भी अपनी भूमिका की तलाश में जुट गई है और उसके द्वारा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मुस्लिम लीग के इस कदम का राज्य की राजनीति पर गहरा असर पड़ना शुरू हो गया है। यह स्थिति सिर्फ केरलम तक सीमित नहीं है, इसके प्रभाव की लहरें उत्तर प्रदेश और आगे चलकर अन्य राज्यों के चुनाव तक पहुंच सकती है। इसके लिये जहां 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू कर दी है, वहीं बसपा से भी कांग्रेस हाथ मिला सकती है। गौरतलब हो, मुस्लिम लीग की यूपी में संभावित चुनावी रणनीति अभी तक मुख्य रूप से सीट-आधारित और गठबंधन-आधारित दिखती है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार केरलम में जीत के बाद कांग्रेस अपने लंबे समय के सहयोगी इंडियन मुस्लिम लीग को दक्षिण के बाहर भी इस्तेमाल करने की रणनीति बना रही है, और उसका सबसे बड़ा टारगेट 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव माना जा रहा है। कांग्रेस द्वारा यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं होता, तो कांग्रेस इंडियन मुस्लिम लीग का यूपी में भरपूर इस्तेमाल कर सकती है। यानी कांग्रेस के मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारने या समर्थन-आधारित दांव की संभावना है। यूपी में लीग का साथ लेकर कांग्रेस इससे सीधे बड़े राज्यव्यापी अभियान की शुरूआत कर कर सकती है, यह गठबंधन किसी बड़े गठबंधन के भीतर सीट-दर-सीट प्रभाव बनाने के लिए हो सकता है। यह रणनीति मुस्लिम मतदाताओं को यह संकेत देने के लिए भी हो सकती है कि पार्टी उनके प्रतिनिधित्व को गंभीरता से ले रही है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस आगे चलकर इंडियन मुस्लिम लीग का बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में भी उपयोग कर सकती है। फिलहाल, यूपी को सबसे बड़ा लक्ष्य बताया गया है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट को लेकर सभी दलों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है, और विश्लेषणों में कहा गया है कि 2027 में मुस्लिम वोट फिर से अहम भूमिका निभा सकता है। इसी कारण कोई भी दल अब केवल प्रतीकात्मक राजनीति नहीं, बल्कि सीधे राजनीतिक लाभ देने वाली रणनीति तलाश रहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मुस्लिम वोटों को लेकर राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी अपने कोर वोट बैंक को बचाने के लिए सक्रिय है, जबकि कांग्रेस, एआईएमआईएम और कुछ हद तक भाजपा भी मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 20 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं। सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाता अपना असर रखते हैं, जिनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30 फीसदी के बीच है, जबकि 73 सीटों पर यह 30 फीसदी से अधिक है। इंडियन मुस्लिम लीग के यूपी में चुनाव लड़ने की बात कहे जाने के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की प्रमुख विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छिड़ गई है। मुस्लिम लीग और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यदि मिलकर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उतरती हैं तो यह समीकरण यूपी की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। एआईएमआईएम ने बिहार और महाराष्ट्र में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर फोकस किया और स्थानीय मुद्दों के साथ आक्रामक संगठन विस्तार किया, जिससे पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी, क्योंकि यूपी में मुस्लिम वोटर परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी के साथ जाता है। फिर भी राजनीतिक पंडितों का मानना है कि केरलम में मुस्लिम लीग की बढ़ती ताकत देखकर यूपी के मुस्लिम समुदाय में एक नई जागृति आ सकती है। यदि मुस्लिम लीग और ओवैसी की पार्टी मिलकर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर एकजुट होकर लड़ती हैं, तो समाजवादी पार्टी का परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक टूट सकता है। अखिलेश यादव ने इस खतरे को भांपते हुए मुस्लिम नेताओं की बैठक बुलाई है। उधर, पिछले कुछ समय से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिली है, उसके बाद सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर अटकलें लगती रहती हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो यहां तक कह दिया कि यूपी में कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। यह बयान सीधे समाजवादी पार्टी पर चोट करने वाला था और इसने दोनों दलों के बीच खटास को और बढ़ा दिया। बहरहाल, इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन अक्सर कागज पर मजबूत गणित दिखाते हैं, लेकिन असल में दलों के बीच विश्वास और कार्यकर्ताओं का तालमेल बहुत जरूरी होता है। 2017 और 2019 के अनुभव बताते हैं कि सपा को इन गठबंधनों से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ और दोनों दलों के वोट बैंक एक-दूसरे में अच्छी तरह स्थानांतरित नहीं हो पाए। ऐसे में कांग्रेस अब बसपा के साथ गठबंधन की संभावनाएं टटोल रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि सपा से कांग्रेस की दूरी का फायदा मायावती को हो सकता है। यह समीकरण यदि बनता है तो यूपी की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। कांग्रेस का दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं पर जोर और बसपा का दलित आधार मिलकर एक नई शक्ति बन सकता है। बात बीजेपी की कि जाये तो उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आने की तैयारी में है, जबकि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में विपक्षी दल का तमगा हटाकर सत्ताधारी दल बनने के लिए मैदान में उतर गई है। इन दोनों के अलावा कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर भी सबकी नजर होगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मिशन-2027 का आगाज कर दिया है और मुसलमानों को जोड़ने की खास योजना बनाई है।

उत्तर प्रदेश में करीब 20 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं। सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाता अपना असर रखते हैं, जिनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30 फीसदी के बीच है, जबकि 73 सीटों पर यह 30 फीसदी से अधिक है।

यदि मुस्लिम लीग और एआईएमआईएम मिलकर यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उतरते हैं तो विपक्षी मतों का बिखराव भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इतिहास यह भी बताता है कि जब-जब मुस्लिम मतदाता बंटे हैं, तब-तब भाजपा ने उसका लाभ उठाया है। ऐसा लगता है कि केरलम में मुस्लिम लीग की बढ़ी ताकत, यूपी में ओवैसी का विस्तार, कांग्रेस-सपा में दरार और बसपा से नये गठबंधन की संभावना। ये सभी मुद्दे मिलकर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देश का सबसे जटिल और रोचक चुनावी मैदान बनाने वाले हैं। यूपी की 403 सीटों पर जो भी समीकरण बनेगा, वह न केवल प्रदेश की, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम वोट का बिखराव किसको फायदा पहुंचाएगा और किसका सियासी किला ढहाएगा।

अजब-गजब

समुद्र की अनोखी मछली 'रेड-लिप्ड बैटफिश'

जिसके होंठों पर गहरे लाल रंग करते हैं आकर्षित

निज संवाददाता : समुद्र में पाए जाने वाली 'रेड-लिप्ड बैटफिश' अपनी अजीब बनावट और अनोखे व्यवहार के कारण दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। मछली को देखकर लगता है जैसे किसी ने इसके होंठों पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगा दी हो। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वैज्ञानिक भाषा में इस मछली को 'ओगकोसेफालस डार्विनी' कहा जाता है। इसका नाम बैटफिश इसलिए रखा गया क्योंकि इसका सिर चमगादड़ की तरह चौड़ा और चपटा दिखाई देता है।यह खास प्रजाति मुख्य रूप से गालापागोस द्वीपों और पूर्वी प्रशांत महासागर के आसपास पाई जाती है। आमतौर पर यह समुद्र की 20 से 40 मीटर गहराई में रहती है, हालांकि कई बार इसे 100 मीटर नीचे तक भी देखा गया है। इस मछली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दूसरी मछलियों की तरह ज्यादा तैरती नहीं है। इसके पेक्टोरल और पेल्विक फिन इतने मजबूत होते हैं कि वे पैरों की तरह काम करते हैं। इन्हीं की मदद से यह समुद्र की सतह पर धीरे-धीरे चलती है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक, ऐसा करने से इसकी ऊर्जा की बचत होती है और यह समुद्र के तल पर आसानी से शिकार की तलाश कर पाती है। रेड-लिप्ड बैटफिश के चमकदार लाल होंठों को लेकर भी वैज्ञानिकों ने खास जानकारी दी है। माना जाता है कि ये लाल होंठ प्रजनन और संचार में मदद करते हैं। समुद्र की गहराइयों में रोशनी बेहद कम होती है, ऐसे में चमकीले रंग साथी को आकर्षित करने का काम करते हैं। यही वजह है कि इसके लाल होंठ इसे बाकी समुद्री जीवों से अलग पहचान दिलाते हैं। इस मछली के सिर पर एक छोटा सा अंग भी होता है, जिसे 'इलिसियम' कहा जाता है। इसके सिरे पर मौजूद चारे जैसी संरचना छोटी मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ही शिकार पास आता है, यह तेजी से हमला कर उसे पकड़ लेती है। वयस्क रेड-लिप्ड बैटफिश की लंबाई करीब 35 से 40 सेंटीमीटर तक हो सकती है।

फाइटर जेट के पायलट करते हैं 4 करोड़ के हेलमेट का इस्तेमाल!

निज संवाददाता : हेलमेट लगाकर वाहन चलाने का संदेश इसलिए दिया जाता है, ताकि सुरक्षित यात्रा हो। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए लोग अच्छा खासा पैसा खर्च भी करते हैं, लेकिन क्या कोई हेलमेट हजार या लाख का नहीं करोड़ों का भी हो सकता है? तो बता दें कि जी हां ऐसे महंगे हेलमेट को फाइटर जेट के पायलट पहनते हैं। दरअसल एफ-35 फाइटर जेट का लाइटनिंग-2 वर्जन दुनिया का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाता है। इस जेट के पायलट जो हेलमेट पहनते हैं, वह दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड वीयरेबल टेक्नोलॉजी वाला होता है, जो बड़े पैमाने पर सैन्य उपयोग के लिए तैयार किया गया है। यह सिर्फ पायलट के सिर की ही सुरक्षा नहीं करता, बल्कि पायलट के लिए पूरा कॉकपिट उसके चेहरे पर ला देता है। इस अद्भुद हेलमेट को हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम (एचएमडीएस) कहा जाता है। इसमें छह कैमरे जेट के शरीर के चारों ओर देखने के लिए लगे होते हैं। ये कैमरे 360 डिग्री का पूरा नजारा लेते हैं और इस एक सिंगल, सीमलेस फीड में बदलकर हेलमेट के वाइजर पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, कि पायलट अगर नीचे देखता हैं, तब जेट के फ्लोर के पार से जमीन दिखाई देती है, जैसे जेट का फर्श पारदर्शी हो। पायलट बिना सिर घुमाए चारों तरफ देख सकता है। यही नहीं इस हेलमेट पर नाइट विजन, टारगेटिंग डेटा, फ्लाइट की स्पीड, ऊंचाई, खतरे की चेतावनी और अन्य जरूरी जानकारी सीधे वाइजर पर दिखाई देती है। ऐसे महज एक हेलमेट की कीमत करीब 4 करोड़ रुपये यानी 4 लाख डॉलर बताई गई है। यह कीमत इसलिए है क्योंकि हर हेलमेट पायलट के

सिर के साइज के हिसाब से तैयार किया जाता है। इसमें हाई-रेजोल्यूशन लेजर स्कैनिंग, 3डी मॉडलिंग और स्पेशल फिटिंग की प्रक्रिया होती है, जिसमें दो दिन लग सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले एडवांस्ड कैमरा, सेंसर, कंप्यूटर प्रोसेसिंग और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी भी बहुत महंगी है। बताया जाता है कि इसके पहले वर्जन (जेन-1और जेन-2) में काफी समस्याएं आईं थीं। इमेज में देरी, हिलने-डुलने की समस्या और रात में हरे रंग की चमक जैसी दिक्कतें आती थीं। इन समस्याओं को देखते हुए इसमें सुधार किया गया और कई साल की मेहनत रंग लाई। अब जेन-3 वर्जन वाले हेलमेट में ज्यादातर समस्याएं दूर हो चुकी हैं। यह हेलमेट फाइटर पायलटों के साथ जेट के इंटरैक्शन को पूरी तरह बदल देता है। पहले कॉकपिट पायलट के चारों ओर होता था, अब पूरा कॉकपिट पायलट के चेहरे पर ही मौजूद होता है। पायलट को हर स्थिति का 360 डिग्री अवेयरनेस मिलता है, जो वार के समय बहुत फायदेमंद बात है। इसके जरिए पायलट अपने दुश्मन को आसानी से ट्रैक कर सकता है और सटीक मिसाइल लांच करने में सफल हो सकता है।

एक ही बच्चे का मां की गर्भ से दो बार हुआ जन्म

निज संवाददाता : चिकित्सा विज्ञान ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। यह अनोखी घटना मेडिकल जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह हैरान करने वाली घटना है एक नवजात शिशु का अपनी जिंदगी बचाने के लिए मां के गर्भ से दो बार जन्म लेना। बच्चे का नाम कैसियन जौबर्ट है, जिसकी जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टरों ने बेहद जोखिम भरी और दुर्लभ सर्जरी का सहारा लिया। इस पूरे मामले को चिकित्सा विज्ञान की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कैसियन की मां के एशर और पिता ग्रेग जौबर्ट को जनवरी 2025 में पता चला था कि उनके घर दूसरा बच्चा आने वाला है।परिवार इस खबर से बेहद खुश था, लेकिन गर्भावस्था के 19वें सप्ताह में डॉक्टरों ने एक गंभीर बीमारी का पता लगाया। जांच में सामने आया कि गर्भ में पल रहे बच्चे को 'कैओस' नाम की बेहद दुर्लभ बीमारी है। इस बीमारी में बच्चे की सांस की नली एक मोटी झिल्ली से बंद हो जाती है, जिससे फेफड़ों में तरल पदार्थ भरने लगता है और अधिकांश मामलों में बच्चे की जान नहीं बच पाती। डॉक्टरों ने पहले गर्भ के भीतर लेजर तकनीक से ब्लॉकेज हटाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने एक बेहद कठिन और जोखिम भरा फैसला लिया।जून 2025 में, जब के एशर 25 सप्ताह की गर्भवती थीं, तब डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उनके पेट को खोला और बच्चे का सिर तथा हाथ बाहर निकाले, जबकि बाकी शरीर गर्भ और प्लेसेंटा से जुड़ा रहा। इसी दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर इमैनुएल ब्लास्तोस ने बच्चे की गर्दन पर बेहद बारीक सर्जरी कर उसकी सांस की नली बनाई। सर्जरी पूरी होने के बाद बच्चे को दोबारा गर्भ में रखकर पेट को सिल दिया गया। करीब दो महीने बाद अगस्त 2025 में कैसियन का सामान्य तरीके से जन्म हुआ। इस तरह यह बच्चा दो बार मां के गर्भ से बाहर आया। जन्म के समय उसका वजन केवल 1.4 किलोग्राम था और उसे चार महीने से ज्यादा समय तक नवजात गहन चिकित्सा इकाई में रखना पड़ा। अब उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

चीन में मिला 4500 साल पुराना विशाल शहर

निज संवाददाता : चीन में 'होउचेंगजुई स्टोन सिटी' नामक प्राचीन स्थल की खुदाई के दौरान लगभग 4500 साल पुराना एक विशाल शहर सामने आया है। यह शहर चीन के उत्तरी क्षेत्र इनर मंगोलिया में पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान मिला है। इस शहर की सबसे बड़ी खासियत इसका जटिल सुरक्षा तंत्र और जमीन के नीचे फैला सुरंगों का नेटवर्क है। पुरातत्वविदों का कहना है कि यह खोज प्राचीन सभ्यताओं की इंजीनियरिंग क्षमता और सैन्य रणनीति को समझने में बेहद अहम साबित हो सकती है। हुन नदी के किनारे स्थित यह प्राचीन शहर करीब 13.8 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब तक की खुदाई में पता चला है कि यह केवल साधारण बस्ती नहीं थी, बल्कि एक मजबूत किलेबंद शहर था। यहां विशाल पत्थर की दीवारें, मजबूत प्रवेश द्वार, गहरी खाइयां और कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी। हालांकि असली रहस्य तब सामने आया जब पुरातत्वविदों ने जमीन के नीचे बनी गुप्त सुरंगों का पता लगाया। खुदाई में अब तक छह बड़ी सुरंगें मिली हैं, जो शहर के केंद्र से अलग-अलग दिशाओं में फैली हुई हैं। इन सुरंगों की बनावट किसी पहिए की तीलियों या मकड़ी के जाले जैसी दिखाई देती है।विशेषज्ञों का मानना है कि इनका इस्तेमाल केवल आवागमन के लिए नहीं, बल्कि युद्ध या हमले के समय रक्षा प्रणाली के रूप में किया जाता था। सुरंगें जमीन से लगभग डेढ़ मीटर से छह मीटर की गहराई पर बनाई गई हैं और उनकी ऊंचाई एक से दो मीटर तक है, जिससे लोग आसानी से अंदर चल-फिर सकें। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये सुरंगें काफी हद तक सुरक्षित बनी हुई हैं। सुरंगों की दीवारों पर आज भी उन औजारों के निशान साफ दिखाई देते हैं, जिनसे इन्हें तराशा गया था।

रिश्ते

बच्चों की परवरिश और पढ़ाई-लिखाई में परेशानी से कौन ज्यादा गुजरती हैं

गृहणियां या कामकाजी मां?

निज संवाददाता : क्या कार्यस्थल के दबाव के साथ परिवार को मैनेज करना आसान है, या घर को मैनेज करना मुश्किल? यह बहस लंबे समय से चल रही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गृहणियों की ज़िंदगी आरामदायक होती है, जबकि बहुत से लोग सोचते हैं कि कामकाजी मांओं की ज़िंदगी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, यह तुलना असल में जितनी आसान लगती है, उतनी है नहीं। दोनों ही मामलों में, महिलाओं को ज़िंदगी के हर पड़ाव पर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बच्चे के जन्म के बाद उनके आस-पास की बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। मांओं की ज़िंदगी पूरी तरह से बच्चे पर केंद्रित हो जाती है। इतने सारे बदलावों को अपनाने का दबाव अक्सर थकान की वजह बनता है। गृहणियों के लिए यह उतना ही मुश्किल है जितना कामकाजी मांओं के लिए। बस संघर्ष का तरीका अलग होता है।बच्चे के जन्म के बाद कई लोगों को थकान होती है। लेकिन अगर यह दिन-ब-दिन बनी रहे, तो इस बारे में सोचना ज़रूरी है। इस थकान के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग होते हैं। कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है, जबकि कुछ का वज़न तेज़ी से कम होता है। उन्हें हर समय बुरा लगता है, नींद नहीं आती, और बिना किसी वजह के दोषी महसूस होता है। इस बारे में देश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हेल्थ के पब्लिश एक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि कई मांएं अपने बच्चों की खुशी और आराम का ध्यान रखते हुए बेघर होने का शिकार हो जाती हैं। ज़्यादातर मामलों में, वे इसे ज़ाहिर नहीं करतीं। लेकिन अंदर ही अंदर चिंता बढ़ती जाती है। यह डिप्रेशन में बदल जाता है। गृहणियों को दिन भर परिवार संभालना पड़ता है। परिवार में सबका ध्यान रखने के साथ-साथ उन्हें अपने बच्चों की भी चिंता करनी पड़ती है। इस बारे में हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल के आंकड़े कहते हैं कि ज़्यादातर गृहणियां अपने बच्चों और परिवार के बाकी लोगों का ध्यान रखते हुए अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचतीं। वे ज़्यादातर समय कोई भी शारीरिक समस्या होने पर उसे छिपाती भी हैं। दिन भर चार दीवारों के अंदर एक ही रूटीन में बंधे रहने के कारण, कई लोगों का बाहरी दुनिया से कम संपर्क होता है। नतीजतन, बोरियत और गंभीर मानसिक डिप्रेशन उन्हें घेर लेता है। कामकाजी मांओं को एक ही समय में दो अलग-अलग दुनिया मैनेज करनी पड़ती हैं- ऑफिस और घर। जब वे ऑफिस में होती हैं, तो ऐसा लगता है कि वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रही हैं, और जब वे अपने बच्चों के साथ होती हैं, तो ऐसा लगता है कि ऑफिस में बहुत काम है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कई कामकाजी मांओं पर की गई एक स्टडी से पता चला है कि ऑफिस में काम खत्म करने की जल्दी, टारगेट पूरा करने का प्रेशर और साथ ही, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियों को संभालने की वजह से वे न सिर्फ़ मेंटली बल्कि फिजिकली भी थक जाती हैं। ऐसे में, कामकाजी मां अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखतीं। समय की कमी, पौष्टिक खाना न खाने और पूरी नींद और आराम न मिलने की वजह से वे हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज़ और माइग्रेन जैसी पुरानी बीमारियों का भी शिकार हो जाती हैं। मां अपनी बिज़ी ज़िंदगी और ज़िम्मेदारियों से कभी थकती नहीं हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब भी मां की भूमिका नहीं बदलती। इसलिए मांओं के लिए अपने शरीर को नज़रअंदाज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। व्यस्त होने के बावजूद भी, उन्हें स्वस्थ रहने का तरीका ढूंढ़ना होता है। उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ काम की ज़िम्मेदारियां बांटनी होती हैं। उन्हें अपनी डाइट और हॉबीज़ का भी ध्यान रखना होता है। उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज़ करनी होती है। अगर मेंटल स्ट्रेस कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेना बेहतर है।

मांओं को कब रहना चाहिए सावधान?

फिजिकल या मेंटल थकान तो होगी ही। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि कहीं यह क्रोनिक स्ट्रेस में तो नहीं बदल रहा। इसलिए, मांओं को कुछ लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए।

1) बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या आसानी से गुस्सा आना।
2) बार-बार सिरदर्द, भूख न लगना, पीठ या शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द।
3) रात में ठीक से न सोना या पूरी नींद लेने के बाद भी बहुत ज़्यादा थकान।
4) बिना किसी वजह के बार-बार रोना, एंग्जायटी, बेवजह घबराहट या कभी-कभी पूरी तरह से इमोशनलेस होना।
5) याददाश्त कमज़ोर होना, हाल की बातें भी भूल जाना।
6) किसी भी विषय पर ध्यान न लगना।

पटरी पर दौड़ने को तैयार देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के क्लब में भारत भी शामिल

निज संवाददाता : भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द ही पटरी पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। रेलवे बोर्ड ने उत्तरी रेलवे के जींद-सोनीपत खंड पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली 10 डिब्बों की इस विशेष ट्रेन को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, 1200 किलोवॉट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रणोदन प्रणाली से लैस यह ट्रेन अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस अनूठी पहल के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो स्वच्छ रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन तकनीक पर काम कर रहे हैं। चूंकि यह तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए दुनिया के गिने-चुने देशों में ही इसका परीक्षण या संचालन किया जा रहा है। देश में इस पर्यावरण-अनुकूल ट्रेन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सरकार इसे तेल आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा के नए विकल्प के रूप में देख रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सरकार ने शुरुआती चरण में ऐसी 35 ट्रेनों के विकास के लिए लगभग 2,800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इन ट्रेनों को मुख्य रूप से उन ऐतिहासिक और पहाड़ी मार्गों पर चलाया जाएगा जहां अभी तक बिजली की लाइनें (विद्युतीकरण) नहीं बिछ पाई हैं। इसके पायलट प्रोजेक्ट के लिए जींद-सोनीपत मार्ग को चुना गया है, क्योंकि जींद में ईंधन भरने और हाइड्रोजन भंडारण की सुविधा उपलब्ध है। इस ट्रेन को मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (डीईएमयू) रेक में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाकर तैयार किया गया है। यह तकनीक हाइड्रोजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनाती है और इससे धुएं के बजाय सिर्फ जल वाष्प (पानी की भाप) उत्सर्जित होती है, जो इसे पारंपरिक ईंधन का सबसे स्वच्छ विकल्प बनाती है। परियोजना की सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) ने साइट पर संपीड़ित हाइड्रोजन गैस के भंडारण और वितरण के लिए जरूरी लाइसेंस जारी कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से हाइड्रोजन संयंत्र और ईंधन भरने वाले पूरे परिसर में अनधिकृत प्रवेश रोकने के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही, हाइड्रोजन रिसाव (लीकेज) और ज्वाला (फायर) डिटेक्टर जैसे सुरक्षा सेंसरों का नियमित निरीक्षण और सफाई की जाएगी ताकि धूल जमा न हो। इस ट्रेन का रख-रखाव दिल्ली के शकूरबस्ती शेड में किया जाएगा और वहाँ ले जाने के लिए इसे किसी अन्य इंजन (लोकोमोटिव) की मदद से निष्क्रिय अवस्था में खींचा जाएगा। सुरक्षित परिचालन के लिए रेलवे ने बेहद सख्त नियम-कायदे तय किए हैं। इसके तहत ईंधन भरने की प्रणाली की चौबीसों घंटे निगरानी होगी और केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित कर्मचारी ही तैनात किए जाएंगे। शुरुआती तीन महीनों तक ट्रेन के सफर के दौरान भी तकनीकी विशेषज्ञ साथ रहेंगे ताकि रास्ते में आने वाली किसी भी समस्या का तुरंत निपटारा किया जा सके।

सांपों के जहर को निष्क्रिय कर सकते हैं ऊंट के आंसू

ताजा वैज्ञानिक शोध का दावा

निज संवाददाता : ताजा वैज्ञानिक शोध में ऊंट के आंसुओं को लेकर चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऊंट के आंसुओं में मौजूद विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज कई खतरनाक सांपों के जहर को निष्क्रिय करने की क्षमता रखती हैं। यदि यह शोध सफल साबित होता है तो भविष्य में सांप के काटने से होने वाली मौतों को कम करने में बड़ी मदद मिल सकती है। यह शोध दुबई स्थित सेंट्रल वेटरनरी रिसर्च लेबोरेटरी और भारत के बीकानेर स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने ऊंटों को सॉ-स्केल्ड वाइपर जैसे बेहद जहरीले सांप के जहर की नियंत्रित मात्रा देकर इम्यूनाइज किया। इसके बाद ऊंटों के खून और आंसुओं के नमूनों की जांच की गई। लैब परीक्षणों में पाया गया कि ऊंट के आंसुओं में मौजूद नैनोबॉडीज जहर के कई घातक प्रभावों को रोकने में सक्षम हैं। इनमें आंतरिक रक्तस्राव, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या और न्यूरोटॉक्सिन का असर शामिल है। शोधकर्ताओं का दावा है कि ऊंट के आंसुओं में मौजूद ये विशेष एंटीबॉडीज करीब 26 प्रकार के जहरीले सांपों के विष को निष्क्रिय कर सकती हैं। इनमें कोबरा, करैत और वाइपर जैसी खतरनाक प्रजातियां शामिल हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, ऊंट से मिलने वाली कैमेलिड एंटीबॉडीज सामान्य एंटीबॉडीज की तुलना में काफी छोटी और अधिक स्थिर होती हैं। यही वजह है कि वे शरीर में तेजी से काम कर सकती हैं। इसके अलावा इन्हें सुरक्षित रखने के लिए अत्यधिक ठंडे तापमान की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में इनके इस्तेमाल की संभावना बढ़ जाती है। भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी सांप के जहर को गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या मानता है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर इलाज नहीं मिलने से हजारों लोगों की जान चली जाती है। मौजूदा एंटीवेनम आमतौर पर घोड़ों या भेड़ों से तैयार किए जाते हैं, जो महंगे होने के साथ कई बार एलर्जी जैसी समस्याएं भी पैदा कर देते हैं। वहीं ऊंट आधारित एंटीवेनम अपेक्षाकृत सस्ता, सुरक्षित और लंबे समय तक टिकाऊ हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऊंट के आंसुओं में प्रोटीन, एंजाइम और लाइसोजाइम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। जब ऊंट को जहर की छोटी मात्रा दी जाती है तो उसका शरीर विशेष एंटीबॉडीज तैयार करता है, जो आंसुओं तक भी पहुंच जाती हैं। यही नैनोबॉडीज विषैले तत्वों को निष्क्रिय करने में मददगार साबित हो सकती हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने साफ किया है कि यह शोध अभी शुरुआती चरण में है और इसे पूरी तरह सफल मानना जल्दबाजी होगी।

रोज पी जाती है 12 से 15 चम्मच पेट्रोल!

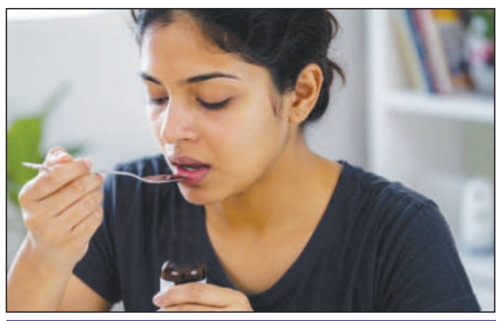

महिला को लगी अजीबो-गरीब लत

निज संवाददाता : लोकप्रिय टीवी शो 'माई स्ट्रेंज एडिक्शन' में कनाडा की रहने वाली 20 वर्षीय शैनन की ऐसी आदत दिखाई गई, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। शैनन को पेट्रोल पीने की लत है और वह रोजाना कई चम्मच पेट्रोल का सेवन करती है। शो में बताया गया कि शैनन ने करीब एक साल पहले पेट्रोल के प्रति आकर्षण महसूस करना शुरू किया था। शुरुआत में वह सिर्फ पेट्रोल की गंध सूंघती थी। इसके बाद वह उंगलियों पर लगे पेट्रोल को चाटने लगी और धीरे-धीरे यह आदत इतनी बढ़ गई कि अब वह रोजाना 12 से 15 चम्मच तक पेट्रोल पी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, वह सालभर में लगभग 19 लीटर से ज्यादा पेट्रोल का सेवन कर लेती है। शैनन का कहना है कि पेट्रोल का स्वाद उसे मीठा, खट्टा और हल्की जलन वाला महसूस होता है। उसके मुताबिक जब वह पेट्रोल पीती है तो शरीर में झुनझुनी और जलन महसूस होती है, लेकिन इसके बावजूद वह खुद को रोक नहीं पाती। उसने बताया कि जब वह तनाव, अकेलापन या डिप्रेशन महसूस करती है, तब पेट्रोल पीने से उसे राहत मिलती है। यही वजह है कि यह आदत धीरे-धीरे उसकी मानसिक निर्भरता बन गई। इस खतरनाक लत ने उसके परिवार की चिंता बढ़ा दी है। परिवार के सदस्य उसे कई बार रोकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वह चोरी-छिपे पेट्रोल पी लेती है। शो में उसके परिवार ने हस्तक्षेप करते हुए उसे इलाज के लिए मनाने की कोशिश की। डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी कि पेट्रोल पीना शरीर के लिए बेहद खतरनाक है और इससे फेफड़े, लीवर, किडनी और मस्तिष्क को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार पेट्रोल में बेंजीन, टोल्यूइन और कई जहरीले रसायन मौजूद होते हैं, जो कैंसर, नसों को नुकसान, सांस संबंधी बीमारियां और आंतरिक अंगों के फेल होने जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। लगातार पेट्रोल पीने से मुंह में छाले, दांतों की खराबी और कई न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो सकती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह आदत जानलेवा साबित हो सकती है। टीवी शो में यह भी दिखाया गया कि शैनन सुबह उठते ही सबसे पहले पेट्रोल पीती है और दिनभर कई बार इसकी चुस्कियां लेती रहती है। रात में सोने से पहले भी वह पेट्रोल का सेवन करती है। उसके मुंह से हमेशा पेट्रोल जैसी गंध आती रहती है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति 'पिका डिसऑर्डर' नामक मानसिक समस्या से जुड़ी हो सकती है। इस बीमारी में व्यक्ति मिट्टी, चॉक, साबुन या अन्य गैर-खाद्य चीजें खाने या पीने की इच्छा महसूस करता है।

मनोरंजन

धर्मेंद्र को मिला पद्म सम्मान

पुरस्कार ग्रहण करते समय हेमा मालिनी के चेहरे पर छलका दर्द

निज संवाददाता : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बीते 25 मई को राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में 2026 के पहले पद्म अवॉर्ड्स दिए। सरकार ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को 131 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की थी। इसी क्रम में पहले फेज में देश की 66 हस्तियों को सम्मानित किया गया और बाकियों को दूसरे चरण में अवॉर्ड दिए जाएंगे। इस खास मौके पर धर्मेंद्र को भी यह पुरस्कार दिया गया। ये सम्मान धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने ग्रहण किया। इस मौके पर हेमा मालिनी के चेहरे पर दर्द और गर्व दोनों दिखा। अब उन्होंने धर्मेंद्र को मिले इस सम्मान में लंबा-चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया है। बता दें कि धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट सेवा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसे ही धर्मेंद्र के नाम का अनाउंसमेंट किया गया और हेमा मालिनी अपनी सीट से उठकर खड़ी हुईं, दर्शकों की भीड़ में बैठीं उनकी बेटी अहाना देओल खुद पर काबू नहीं रख सकीं और बिलखती हुई नजर आईं। हेमा मालिनी ने इस अवॉर्ड समारोह की कुछ स्पेशल झलकियों के साथ धर्मेंद्र को मिले पद्म विभूषण सम्मान के लिए अपने मन की बातें भी कहीं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा-एक बेहद खुशी का पल! एक ऐसा पल जब मैंने सचमुच अपने पति धरम जी की गर्मजोशी भरी मौजूदगी महसूस कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मेरा हाथ थामे हुए हैं और मुझे उस मंच तक ले जा रहे हैं जहां पद्म विभूषण पुरस्कार उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने आगे लिखा-कल पद्म पुरस्कार समारोह में जब महामहिम राष्ट्रपति ने स्वयं योग्य विजेताओं को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए, मैं धरम जी का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठी थी और मेरे भीतर अपार गर्व का भाव उमड़ आया। उनके साथ बिताए कई बरसों की यादें, पहले कई हिट फिल्मों में को-स्टार्स के रूप में और बाद में उनके जीवन साथी के रूप में। इन विचारों से मेरी आंखों में आंसू आ गए। वे एक प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले पति, एक स्नेही पिता और दादा, एक नेक दोस्त, सच्चे दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए अपने इमोशंस को बयां करते हुए कहा-धरम जी ने इन सभी महान गुणों और उससे भी कहीं अधिक गुणों का उदाहरण पेश किया है। वे एक उदार, दयालु और अच्छे इंसान थे, जिन्हें जानने वाले सभी लोग पहचानते और प्यार करते थे। मैंने अपने पूरे परिवार, उनके लाखों फैन्स और चाहने वालों की ओर से पूरी विनम्रता के साथ यह पुरस्कार स्वीकार किया।

मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे एक अद्भुत जीवनसाथी दिया, जिनकी यादें मैं जीवन भर संजो कर रखूंगी। ये मेरे सच्चे भाव हैं, देश के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, पद्म विभूषण को धर्म जी की ओर से प्राप्त करने के इस क्षण से मैं अभिभूत हूं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ने इस साल 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। इनमें पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं। इस दिन के समारोह में उन्होंने दो पद्म विभूषण, छह पद्म भूषण और 58 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। जानकारी के मुताबिक शेष पद्म पुरस्कार बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।

'खईके पान बनारसवाला' गाने ने 'डॉन' को बनाया 'ब्लॉकबस्टर'

निज संवाददाता : अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं। बॉलीवुड के इस शहंशाह ने 50 सालों से ज्यादा के करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं जो आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं। उनके हर किरदार ने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। जानकर हैरानी होगी कि उनकी 70 लाख रुपये के बजट में बनी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को पहले हफ्ते में ही फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन फिर फिल्म के एक गाने ने ऐसी धूम मचाई की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास ही रच दिया। जानते हैं ये फिल्म कौन सी थी?पहले हफ्ते में फ्लॉप घोषित होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई करने वाली अमिताभ बच्चन की यह फिल्म डॉन है। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी और आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इसे चंद्रा बरोट द्वारा निर्देशित और सलीम-जावेद की कहानी पर आधारित और नरिमन ईरानी द्वारा प्रोड्यूर फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल प्ले किया था। उनके साथ फिल्म में जीनत अमान, प्राण, इफ्तेखार, ओम शिवपुरी और सत्येन कप्पू भी थे। डॉन एक मच अवेटेड फिल्म थी हालांकि इसे 1978 में बिना किसी प्रमोशन के रिलीज़ कर दिया गया था। वहीं सिनेमाघरों में पहले हफ्ते में इसे दर्शकों ने नहीं पूछा और ये फिल्म फ्लॉप घोषित कर दी गई थी। लेकिन एक गाने ने इसे जबरदस्त हिट बना दिया था।दरअसल फिल्म को हिट बनाने में इसके गाने खाइके पान बनारसवाला ने बड़ा रोल प्ले किया था। इस गाने को मेकर्स ने फिल्म के रिलीज़ होने के बाद जोड़ा था। इस एक गाने ने डॉन की बॉक्स ऑफिस पर जैसे किस्मत ही बदल दी और स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत यह फिल्म ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। 75 लाख के बजट में बनी डॉन सुपरहिट साबित हुई और इसने भारी मुनाफा कमाया। अमिताभ बच्चन, ज़ीनत अमान और चंद्रा बरोट ने फिल्म डॉन के लिए कोई सैलरी नहीं ली थी लेकिन फिल्म की सफलता ने उन्हें लोगों के दिलों में अमर कर दिया। डॉन ने खासतौर पर अमिताभ बच्चन को सुपरस्टारडम तक पहुंचाने में मदद की थी। बता दें कि 1978 में रिलीज़ हुई डॉन उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी थी और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे गोल्डन जुबली घोषित किया गया था। अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7.2 करोड़ रुपये कमाए थे। इनफ्लेमेशन को ध्यान में रखते हुए, आज यह राशि 250 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी।

'49 साल की उम्र में भी वो 25 साल की लड़कियों से ज्यादा हॉट...'

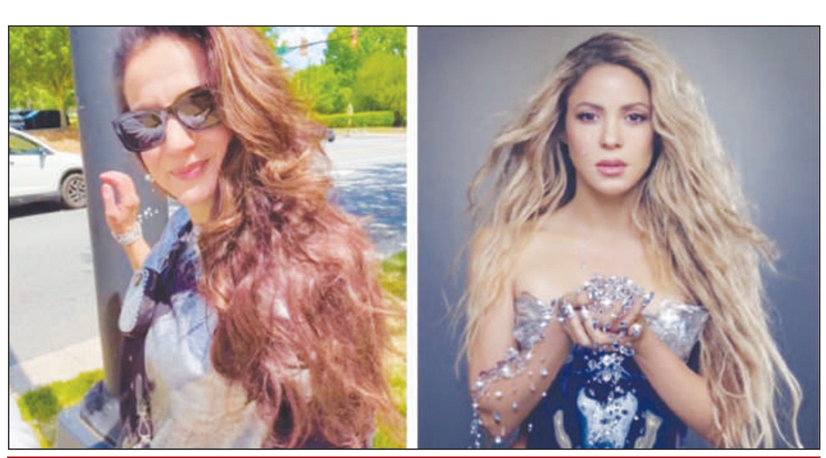

अमीषा पटेल ने बांधे शकीरा की तारीफ के पुल

निज संवाददाता : अभिनेत्री अमीषा पटेल इन दिनों सोशल मीडिया पर दो बातों को लेकर काफी चर्चा में हैं। पहली वजह है पॉप स्टार शकीरा की तारीफ करना और दूसरी वजह है बॉलीवुड के नए कलाकारों पर गुस्सा निकालना। अमीषा ने शकीरा की उम्र को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो फैंस के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। मशहूर सिंगर शकीरा ने फीफा विश्व कप 2026 के ऑफिशियल गाने दाई दाई से धमाकेदार वापसी की है। इस गाने में उनके साथ नाइजीरियाई सिंगर बर्ना बॉय भी हैं। गाने के एक वीडियो में शकीरा पीले रंग के कपड़ों में शानदार डांस करती नजर आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए अमीषा पटेल ने लिखा-वाह शकीरा, आप 49 साल की उम्र में भी कमाल हैं। आपका डांस, ड्रेस और लुक 25 साल की उम्र से भी ज्यादा हॉट और खूबसूरत है। दूसरी तरफ, अमीषा ने आज के दौर के नए बॉलीवुड कलाकारों और उनके काम करने के तरीके पर तीखा निशाना साधा है। अमीषा का कहना है कि आज का बॉलीवुड एक्टिंग और मेहनत से ज्यादा दिखावे, सोशल मीडिया और पीआर पर भरोसा कर रहा है। यह साल 2026 है, साल 2000 नहीं। आज के समय में फिल्मों के लिए 100 करोड़ रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। अमीषा ने अपनी पुरानी कामयाबियों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कहो ना प्यार है, गदर 1 और गदर 2 जैसी तीन बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है। ये फिल्में उनके साथ काम करने वाले को-स्टार्स के करियर की भी सबसे बड़ी हिट फिल्में हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वह दूसरी अभिनेत्रियों की तरह खुद की झूठी तारीफ करवाने के लिए पैसे देकर पीआर कंपनियों का इस्तेमाल नहीं करतीं।

नीतू कपूर की होगी फिल्म इंडस्ट्री में वापसी

निज संवाददाता : दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर की फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की टीवी अभिनेत्री रुबीना दिलैक ने खुलकर सराहना की है। एक्ट्रेस रुबीना ने कहा कि वह नीतू कपूर की जिंदगी और उनके संघर्षों से खुद को गहराई से जोड़कर देखती हैं। उन्होंने कहा कि नीतू कपूर ने यह साबित कर दिया है कि जिंदगी में बड़े बदलावों के बाद भी महिलाएं दोबारा अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं और नई शुरुआत कर सकती हैं। एक महिला, मां और कामकाजी प्रोफेशनल के तौर पर नीतू कपूर की वापसी उन्हें बेहद प्रेरित करती है। हाल ही में एक बातचीत के दौरान रुबीना ने कहा कि नीतू कपूर सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि साहस और आत्मविश्वास की भी मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि सालों से लोगों ने देखा है कि नीतू कपूर ने जीवन की हर चुनौती का मजबूती से सामना किया है। पति ऋषि कपूर के निधन के बाद उनका दोबारा फिल्मों में लौटना कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया है।रुबीना का मानना है कि महिलाओं को इसी तरह आगे बढ़कर समाज में अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। रुबीना ने कहा कि मां बनने या जिंदगी में बड़े बदलाव आने के बाद अक्सर महिलाएं अपने करियर को लेकर असमंजस में रहती हैं, लेकिन नीतू कपूर ने यह दिखा दिया कि अगर इच्छा और आत्मविश्वास हो तो वापसी हमेशा संभव है। उन्होंने कहा कि नीतू कपूर ने महिलाओं के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया है और यह संदेश दिया है कि उम्र या परिस्थितियां किसी महिला की पहचान तय नहीं करतीं। अभिनेत्री ने नीतू कपूर की उस बात का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी वापसी सिर्फ काम करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह जानने के लिए थी कि क्या इतने सालों बाद भी कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास कायम है।

रुबीना ने इसे बेहद प्रेरणादायक बताया और कहा कि हर इंसान को समय-समय पर खुद को परखना चाहिए। इस दौरान रुबीना ने अपने पति अभिनव शुक्ला की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि अभिनव घर पर हकर उनके जुड़वां बच्चों की देखभाल कर रहे हैं ताकि वह अपने करियर पर ध्यान दे सकें।

स्वामी मोहता पब्लिशिंग हाउस के लिए, प्रकाशक, मुद्रक : अजय कुमार मोहता द्वारा अरिहंत मुद्रा, 61, सूर्यसेन स्ट्रीट, कोलकाता-700009 से मुद्रित एवं प्रकाशित। **संपादकीय कार्यालय :** 10, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, (क्लाइब रो), 5बी मंजिल, रूम नं. 9, कोलकाता-700001, **स्थानीय कार्यालय :** 28-5 कन्वेंट रोड, मौलाली, कोलकाता-700014। **संपादक : अजय कुमार मोहता**, मो. 9830045693, E-mail-gambheersamachar@gmail.com. Website. www.gambheersamachar.in (प्रकाशित रचनाओं के चयन, संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी, सभी कानूनी विवाद के लिए कोलकाता न्याय क्षेत्र)